RNI No. RAJHIN/2001/05699

जनता की भावनाओं एवं आकांक्षाओं का एकमात्र समाचार-पत्र

हैलो सरकार

www.hellosarkar.com

पल-पल की टी.वी. एवं रेडियो खबरों के लिए लॉन ऑन करें- www.hellosarkar.com

हैलो सरकार समाचार पत्र में नियमित पाठक बनने, समाचार की प्रति मंगवाने व विज्ञापन देने हेतु सम्पर्क करें
फोनः 0141-2202717
मोः 9214203182
वाट्सप नं. 9928078717

सुविचार

खुद का अपमान कराके जीने से तो अच्छा मर जाना है क्योंकि प्राणों के त्यागने से केवल एक ही बार कष्ट होता है पर अपमानित होकर जीवित रहने से आजीवन दुःख होता है।

-चाणक्य

वर्ष-25 अंक-267 दैनिक प्रभात संस्करण जयपुर, रविवार 31 मई, 2026 पृष्ठ-4 मूल्यः 2.50

भ्रष्ट आचरण के दलदल से दूर रहें कार्मिक, जन सेवा को बनाएं ध्येय -मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर । मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प को पूरा करने में कार्मिकों की अहम भूमिका है। ईमानदारी और पारदर्शिता से किया गया कार्य ही सुशासन की पहचान बनता है। इसलिए जनता को समय पर सेवाएं देकर कार्य संस्कृति को मजबूत बनाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने आह्वान किया कि कार्मिक अपनी सेवा में पूर्ण शुचिता को अपनाएं और भ्रष्ट आचरण के दलदल से दूर रहकर जन सेवा के ध्येय को और अधिक मजबूत बनाएं।

मुख्यमंत्री शनिवार को जयपुर के आरआईसी में आयोजित राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के नवम महाधिवेशन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 'न खाऊंगा और न खाने दूंगा' के मूलमंत्र पर चलते हुए हमने 103 अधिकारियों को निलंबित किया है, 6 अफसरों को सेवा से बर्खास्त किया है और 11 भ्रष्ट अधिकारियों की आजीवन पेंशन पर रोक लगाई है। वहीं रिश्वत, ट्रैप, पद का दुरुपयोग, आय से अधिक संपत्ति प्रकरणों के 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति दी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत 37 अन्य प्रकरणों में भी कठोर कार्रवाई की है।

उन्होंने कहा कि स्वच्छता और बेहतर नागरिक सुविधाएं शहर की पहचान होती हैं। प्रदेश के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाये रखने में नगर पालिका कर्मचारी सबसे महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जो हर समय जनता की सेवा में जुटे रहते हैं। उन्होंने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर नगर निगम ने पूरे देश में 16वां स्थान प्राप्त किया, वहीं 3 लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उदयपुर 13वें स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें प्रदेश के शहरों को स्वच्छता में देश में अग्रणी बनाने के लक्ष्य के साथ काम करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत मिशन की पहल देश में आज जन आंदोलन बन चुकी है। इस अभियान के माध्यम से लोगों की स्वच्छता की आदतों में बदलाव आया है। वहीं, घर-घर में शौचालय बनवाकर हमारी माता-बहनों के जीवन को एक गरिमा प्रदान की गई है। साथ ही, शहरों में अच्छे बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए स्मार्ट सिटी मिशन प्रारंभ किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से देशभर में जल संचय-जनभागीदारी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को सशक्त बनाने के क्रम में राज्य में गत वर्ष की भांति इस वर्ष भी वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके साथ ही हमारी सरकार ने हरियालो राजस्थान अभियान में अभी तक प्रदेशभर में लगभग 20 करोड़ पौधे लगाए हैं और इस वर्ष भी 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया है। इसके तहत प्रदेश में पहली बार चंदन वन भी विकासित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से ऊर्जा की बचत और मितव्ययिता को अपनाने का आह्वान किया है, जिसमें हम सभी अपना सहयोग दे रहे हैं।

मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार तकनीक, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ आगे बढ़ते हुए स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित शहरों के निर्माण के लिए कार्य कर रही है। इसी दिशा में पेयजल, सीवरेज, ड्रेनेज तथा डिजिटल नगर सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। अमृत 2.0 के तहत 11 हजार 560 करोड़ रुपये की राशि से राज्य के 200 शहरों और कस्बों में 363 परियोजनाओं पर काम हो रहा है। शहरी क्षेत्रों के लिए नई टाउनशिप नीति 2024 लागू की गई है। हमारा लक्ष्य है कि शहरों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही आधुनिक सफाई व्यवस्था और ठोस कचरा प्रबंधन सुदृढ़ हो।

उन्होंने ने कहा कि आमजन का सबसे पहला और सीधा संपर्क नगर निकाय के कर्मचारियों से ही होता है। ये सफाई, पेयजल, सड़क से लेकर सीवर, पार्कों का रखरखाव, अग्निशमन व जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं के माध्यम से जनता के जीवन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं। तेजी से बढ़ते शहरीकरण के इस दौर में आने वाले वर्षों में नगर निकायों की भूमिका और भी अधिक निर्णायक, व्यापक और महत्वपूर्ण होने जा रही है। ऐसे में वे सभी अपनी सेवा और समर्पण की भावना से प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए पानी और बिजली के क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं को धरातल पर उतारा जा रहा है। राइजिंग राजस्थान के तहत लगभग 9 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने एसआईटी और एजीटीएफ का गठन किया, प्रदेश में पेपरलीक पर लगाम लगाई तथा युवाओं को निरंतर नौकरी के अवसर उपलब्ध करवा रहे हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री ने कर्मचारी कल्याण स्मारिका का विमोचन किया।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने कहा कि राजस्थान को मुख्यमंत्री के रूप में एक किसान पुत्र का नेतृत्व प्राप्त हुआ है, जिन्होंने किसानों के कल्याण और प्रदेश के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही सहायता के साथ ही राज्य सरकार ने प्रदेश के किसानों की सम्मान निधि में वृद्धि की है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लगातार गांवों और शहरों में जाकर आमजन से संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रहे हैं। राज्य सरकार 'वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान' एवं 'हरियालो राजस्थान' के माध्यम से प्रदेश को हराभरा बनाने तथा जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है।

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास, सुशासन और जनकल्याण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। जल प्रबंधन, ऊर्जा, युवाओं के हित, कर्मचारी कल्याण तथा आधारभूत संरचना के विकास जैसे क्षेत्रों में राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। मुख्यमंत्री के कुशल नेतृत्व में प्रदेश 'विकसित राजस्थान-2047' के लक्ष्य की ओर दृढ़ता से अग्रसर है।

इस अवसर पर स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन तथा राजस्थान नगर पालिका कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेशाध्यक्ष भागचंद श्रीमाल सहित अन्य पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे।

जयपुर में महिला ने परिचित युवक का काटा प्राइवेट पार्ट

हैलो सरकार न्यूज

जयपुर। राजधानी जयपुर के ज्योति नगर थाना क्षेत्र में शनिवार शाम एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां एक महिला ने अपने परिचित युवक पर ब्लेड से हमला कर दिया। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे उपचार के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महिला का आरोप है कि युवक ने उसके साथ जबरदस्ती और बलात्कार का प्रयास किया था, जिसके बचाव में उसने यह कदम उठाया। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आरोपी महिला को डिटेन किया है, उससे पूछताछ की जा रही है।

पुलिस के अनुसार शनिवार शाम एक 33 वर्षीय महिला ने पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी कि एक युवक पानी पीने के बहाने उसके घर में घुस आया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। घर के अंदर युवक लहूलुहान हालत में मिला। उसके गले और निजी अंग पर धारदार वस्तु से वार किए गए थे। पुलिस ने तत्काल उसे एसएमएस अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है।

दोनों के अलग-अलग आरोप

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला और घायल युवक कई सालों से एक-दूसरे के परिचित हैं। शनिवार शाम युवक महिला से मिलने उसके घर पहुंचा था। इसके बाद दोनों के बीच क्या हुआ, इसे लेकर दोनों पक्षों के अलग-अलग दावे हैं, जिनकी पुलिस जांच कर रही है।

अकेला पाकर बलात्कार करने की कोशिश का आरोप

महिला का आरोप है कि युवक

ने उसे घर में अकेला पाकर बलात्कार करने की कोशिश की। विरोध करने और खुद को बचाने के लिए उसने ब्लेड से युवक पर वार कर दिया। घटना के बाद महिला ने स्वयं पुलिस को सूचना देकर पूरी घटना की जानकारी दी।

हाल ही में युवक की हुई थी शादी

वहीं जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती युवक ने महिला के खिलाफ जानलेवा हमला करने की शिकायत दर्ज कराई है। युवक का आरोप है कि महिला ने उस पर हमला किया और उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि युवक की हाल ही में शादी हुई है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है।

विश्व तंबाकू निषेध दिवस (31 मई) भारत में हर साल तंबाकू से 10 लाख मौतें

जयपुर। हर साल 31 मई को संपूर्ण विश्व में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू के सेवन से मानव स्वास्थ्य पर होने वाले जानलेवा प्रभावों, बीमारियों, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को पहुंचने वाली गंभीर क्षति के प्रति वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाना है। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ. लियाक़त अली मंसूरी ने इस अवसर पर आमजन से तंबाकू मुक्त समाज के निर्माण की अपील की है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष विश्व स्वास्थ्य संगठन (द्वारा घोषित आधिकारिक विषय (आकर्षण का पर्दाफाश- निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला रखा गया है। यह विषय पारंपरिक तंबाकू के साथ-साथ आधुनिक निकोटीन उत्पादों के जरिए युवाओं को जाल में फंसाने वाले उद्योगों के नए रूपों को बेनकाब करने पर केंद्रित है।

तंबाकू नियंत्रण की वैश्विक चुनौतियों को समझने के लिए प्रतिवर्ष विशेष थीम निर्धारित की जाती है, जो इस प्रकार हैं-

वर्ष 2026 की थीम- आकर्षण का पर्दाफाश करना – निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना। वर्ष 2025 की थीम- ब्राइट प्रोडक्ट्स, डार्क इंटेंशंस – अनमास्किंग दी अपील। वर्ष 2024 की थीम- बच्चों को तंबाकू उद्योग के हस्तक्षेप से बचाना।

दुनिया के 12% धूम्रपान करने वाले भारत में

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार, पूरी दुनिया में हर साल लगभग 80 लाख लोग तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के कारण असमय काल का ग्रास बनते हैं।

दिल्ली में बड़ा हादसा, महरौली में पांच मंजिला इमारत गिरी, कई लोगों के दबने की आशंका

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में शनिवार शाम मौसम ने अचानक करवट ली। कई इलाकों में तेज बारिश हुई, धूल भरी आंधी चली और इसी बीच राजधानी के महरौली इलाके से एक बेहद दुखद खबर सामने आई। महरौली के सैदुलाजब इलाके में एक पांच मंजिला इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई।मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तेज आवाज के साथ बिल्डिंग नीचे आ गिरी। आसपास मौजूद लोग पहले तो कुछ समझ ही नहीं पाए। धूल का बड़ा गुबार उठ गया और लोग मदद के लिए इधर-उधर भागने लगे। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर विभाग को इस घटना की सूचना दी।

कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका

सूचना मिलते ही राहत और बचाव टीमें मौके पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं। पुलिस, दमकल कर्मी और बचावकर्मी लगातार मलबा हटाने में जुटे हुए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार, इमारत के अंदर कई लोग मौजूद थे और कुछ लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अब तक कम से कम चार लोगों को जिंदा बाहर निकाल लिया गया है। घायलों को तुरंत एंबुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। बचावकर्मी बेहद सावधानी के साथ काम कर रहे हैं क्योंकि मलबा काफी ज्यादा फैला हुआ है और किसी भी तरह की जल्दबाजी खतरा बढ़ा सकती है।

10 हजार की रिश्वत लेते ब्रांच मैनेजर रंगे हाथों गिरफ्तार

कर्मचारी के मेडिकल बिल पास करने के बदले मांगी थी घूस

चित्तौड़गढ़ । चित्तौड़गढ़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को चित्तौड़गढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की शाखा प्रबंधक संदीपा वोहरा को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारी पर एक कर्मचारी के मेडिकल बिल और अवकाश भुगतान स्वीकृत करने के बदले रिश्वत मांगने का आरोप है। एसीबी को मिली शिकायत और खुफिया सूचना के अनुसार, हिन्दुस्तान जिंक चंदेरिया में कार्यरत एल एंड टी कंपनी का एक कर्मचारी वर्ष 2025 में ड्यूटी के दौरान लकवाग्रस्त हो गया था। कर्मचारी के उपचार से जुड़े मेडिकल बिलों और मेडिकल अवकाश के भुगतान की प्रक्रिया लंबित थी।

लगातार रिश्वत मांग रही थी शाखा प्रबंधक

आरोप है कि इन दावों को स्वीकृत करने के एवज में ईएसआईसी की शाखा प्रबंधक संदीपा वोहरा लगातार रिश्वत की मांग कर रही थीं। यह दबाव कर्मचारी के परिजनों और कंपनी के एचआर प्रबंधक पर भी बनाया जा रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसीबी के उप महानिरीक्षक डॉ. रामेश्वर सिंह के निर्देशन में शिकायत का सत्यापन कराया गया। जांच के दौरान रिश्वत मांगने के आरोप सही पाए गए। इसके बाद एसीबी स्पेशल यूनिट उदयपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल जोशी के नेतृत्व में ट्रैप की योजना बनाई गई।

विज्ञापन

10 हजार की रिश्वत लेते धराई महिला अधिकारी

शनिवार को परिवादी तय राशि लेकर शाखा कार्यालय पहुंचा। जैसे ही आरोपी अधिकारी ने 10 हजार रुपये की रिश्वत स्वीकार की, एसीबी की टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। टीम ने रिश्वत की पूरी राशि भी बरामद कर ली। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी अधिकारी पर पहले भी कर्मचारियों के विभिन्न क्लेम पास करने के बदले अवैध राशि लेने के आरोप लग चुके हैं। एसीबी अब इस पहलू की भी जांच कर रही है।

फिलहाल आरोपी महिला अधिकारी से पूछताछ जारी है। एसीबी अधिकारियों के अनुसार मामले से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर उनके कार्यालय एवं अन्य ठिकानों पर भी तलाशी की कार्रवाई की जा सकती है।

शिक्षाविद् सुभाष जोशी और लेखा विशेषज्ञ दिनेश चुरा को पीएचडी की मानद उपाधि

बीकानेर । यूनाइटेड स्टेट ऑफ़ अमेरिका के सीडर ब्रूक विश्वविद्यालय द्वारा बीकानेर के शिक्षाविद् सुभाष जोशी और लेखा विशेषज्ञ दिनेश चुरा को पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की गई है। अखिल भारतीय पुष्टिकर सेवा परिषद (युवा) के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. जी. बिस्सा ने बताया कि पीएम श्री राजकीय सादुल उच्च माध्यमिक विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक एवं शिक्षाविद् सुभाष जोशी को शिक्षा के क्षेत्र में तथा स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कोषाधिकारी दिनेश चुरा को लेखा के क्षेत्र में पीएचडी की मानद उपाधि प्रदान की गई है। बिस्सा ने बताया कि शनिवार को नई दिल्ली के मेपल गोल्ड बैंक्वेट्स के रेडिसन ब्लू होटल में आयोजित दीक्षांत समारोह में जोशी और चुरा को यह मानद उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम में संबंधित विश्वविद्यालय के अधिकारियों के साथ पूर्व सांसद दीप सिंह राठौड़ एवं भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ़ अफेयर्स विभाग के उपनिदेशक रघुवीर शर्मा तथा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ प्रभात कुमार एवं नेपाल से आए विश्व गुरु डॉ गौरी शंकर महाराज की उपस्थिति में यह उपाधि प्रदान की गई।

होटल और रेस्टोरेंट के लिए नई लाइसेंस फीस नीति लागू, कैटेगरी में बड़ा बदलाव

जयपुर। राजस्थान सरकार ने होटल और रेस्टोरेंट के लिए नई वार्षिक लाइसेंस फीस लागू कर दी है। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत श्रेणियां घटाकर सरल की गई हैं। अब शुल्क होटल के कमरों, सुविधाओं और रेस्टोरेंट की क्षमता के आधार पर तय होगा। राजस्थान में होटल और रेस्टोरेंट संचालकों के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने लाइसेंस फीस का नया ढांचा लागू कर दिया है। केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत होटल और रेस्टोरेंट की श्रेणियों का पुनर्गठन करते हुए नई वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। पहले होटलों की स्टार रेटिंग और विभिन्न सुविधाओं के आधार पर कई श्रेणियां निर्धारित थीं, लेकिन अब उन्हें केवल पांच कैटेगरी में बांटा गया है। इसी प्रकार रेस्टोरेंट्स के लिए भी श्रेणियों की संख्या घटाकर तीन कर दी गई है। नई व्यवस्था में होटलों का वर्गीकरण कमरों की संख्या और उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर किया जाएगा। नई दरों के अनुसार 50 कमरों तक के होटल के लिए नगर निगम क्षेत्र में 25 हजार रुपये, नगर परिषद क्षेत्र में 20 हजार रुपये और नगर पालिका क्षेत्र में 15 हजार रुपये वार्षिक लाइसेंस फीस निर्धारित की गई है। वहीं 51 से 100 कमरों वाले होटलों के लिए यह शुल्क क्रमशः 50 हजार, 40 हजार और 18 हजार रुपये तय किया गया है।

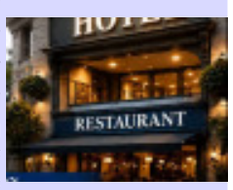

स्विमिंग पूल, जिम, स्पा और अन्य लग्जरी सुविधाओं से युक्त 100 कमरों तक के होटलों के लिए नगर निगम क्षेत्र में 75 हजार रुपये, नगर परिषद क्षेत्र में 60 हजार रुपये और नगर पालिका क्षेत्र में 55 हजार रुपये फीस निर्धारित की गई है। इसी तरह 150 कमरों तक वाले लग्जरी होटलों के लिए नगर निगम क्षेत्र में 1 लाख रुपये, नगर परिषद क्षेत्र में 80 हजार रुपये और नगर पालिका क्षेत्र में 70 हजार रुपये शुल्क तय किया गया है। 150 से अधिक कमरों वाले बड़े होटलों के लिए यह फीस क्रमशः 1.50 लाख रुपये, 1.25 लाख रुपये और 1 लाख रुपये होगी।

सराहनीय सेवाओं के लिए 123 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को मिलेगा डीजीपी डिस्क एवं प्रशस्ति रोल

हैलो सरकार न्यूज, जयपुर। पुलिस मुख्यालय ने अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था, प्रशासन, खुफिया कार्यों, साइबर अपराध नियंत्रण, यातायात प्रबंधन तथा उत्कृष्ट पुलिसिंग में उल्लेखनीय योगदान देने वाले 123 पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को महानिदेशक पुलिस डिस्क एवं प्रशस्ति रोल प्रदान करने की घोषणा की है।

महानिदेशक पुलिस श्री राजीव कुमार शर्मा द्वारा जारी आदेश में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस स्तर से लेकर कांस्टेबल तक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है। पुलिस मुख्यालय के स्थायी आदेश 2/2016 के तहत यह सम्मान विभाग में उत्कृष्ट एवं सराहनीय कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। चयन समिति की अनुशंसा पर विभिन्न रेंज, जिलों एवं इकाइयों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर इस वर्ष कुल 123 अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चयन किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी (एडीजी, आईजी और डीआईजी रैंक)

सम्मानित होने वालों में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एचजीआर सुहास, महानिरीक्षक पुलिस राजेंद्र सिंह (द्वितीय बार), राहुल प्रकाश (तृतीय बार), परिस देशमुख, उप महानिरीक्षक पुलिस जय यादव (तृतीय बार), मनोज कुमार और शांतनु कुमार सिंह के नाम शामिल हैं, जिन्हें उनकी विशिष्ट एवं सराहनीय सेवाओं के लिए इस प्रतिष्ठित पदक से नवाजा जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपायुक्त

✦फील्ड पुलिसिंग और जिला स्तर पर कप्तानी व कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने वाले अधिकारियों में सुमित मेहरडा, संजीव नैन, विकास सांगवान (तृतीय बार), अमित कुमार (द्वितीय बार), रतन सिंह, तेजस्वनी गौतम (तृतीय बार), बी. आदित्य, हरी शंकर, अनिल कुमार, दिगंत आनन्द (तृतीय बार), विशाल जांगिड और प्रवीण नायक नूनावत (द्वितीय बार) के नाम शामिल हैं, जिन्हें उत्कृष्ट प्रशासनिक क्षमताओं और बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीजीपी डिस्क प्रदान की जा रही है।

✦अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उप अधीक्षक

✦विधिक अनुसंधान, तकनीकी विंग और विभिन्न महत्वपूर्ण शाखाओं में प्रभावी कार्य करने वाले अधिकारियों में अतिरिक्त पुलिस आयुक्त योगेश दाधीच, डॉ. राजीव पचार, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त आलोक कुमार सिंघल (द्वितीय बार), ललित किशोर शर्मा (द्वितीय बार), अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीक्षा कामरा (तृतीय बार), अदिति कॉवत, भंवरलाल और सौरभ तिवारी के नाम शामिल हैं।

✦इनके साथ ही सहायक पुलिस अधीक्षक अजेय सिंह राठौड, पंकज यादव, हरिशंकर शर्मा, सोन चन्द वर्मा, सहायक निदेशक अभियोजन भंवर कुलदीप राठौड, पुलिस उप अधीक्षक और वृत्ताधिकारी के रूप में डॉ0 पूनम, मनीष शर्मा, हर्षराज सिंह और राजावत प्रेम कुमार को भी इस सम्मान के लिए चुना गया है।

पुलिस निरीक्षक रैंक

✦जमीनी स्तर पर थानों की कमान संभालने वाले और विभिन्न पुलिस विंग्स में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले समर्पित पुलिस निरीक्षकों की सूची में देवेन्द्र सिंह (द्वितीय बार), भुटाराम (द्वितीय बार), विष्णु शर्मा, राजेन्द्र प्रसाद, सरोज बैरवा, चन्द्रभान सिंह, दिनेश सारण, लक्ष्मी कराड़िया, मनोज चौहान, प्रभुनारायण मीणा, पवन कुमार चौबे (द्वितीय बार), रमेश कविया, बलवन्त राम, अशोक बिश्नोई और रमेश चंद आर्य के नाम समाहित हैं।

उप निरीक्षक रैंक

✦अपराधों के खुलासे, धरपकड़ और फील्ड इंटेलिजेंस को मजबूत करने वाले जांबाज पुलिस उप निरीक्षकों में शैलेंद्र कुमार शर्मा, धर्मसिंह, भरत लाल, राधेश्याम वर्मा, सुरेन्द्र सिंह, संदीप बसेरा, यमनेश कुमार शर्मा, रविन्द्र सिंह, यशपाल सिंह चौधरी और राजवीर के नाम सम्मान के साथ शामिल हैं।

✦सहायक उप निरीक्षक रैंक

विभिन्न कार्यालयों और पुलिस थानों में अनुसंधान व विधिक प्रक्रियाओं को तत्परता से पूरा करने वाले सहायक उप निरीक्षकों की सूची में देवकरण, दिनेश कुमार, कमलेन्द्र सिंह, जसवन्त सिंह, खड़ग सिंह, सूरज बाली और जगदीश प्रसाद के नाम शामिल हैं।

हेड कांस्टेबल रैंक

विभिन्न जिलों, विशेष शाखाओं और थानों में अनुसंधान व कानून-व्यवस्था में महत्वपूर्ण सहयोग देने वाले हेड कानिस्टेबलों में शाहिद अली, शहनाज खान, हिम्मत सिंह, राजेश कुमार, वेदप्रकाश, अरविन्द सिंह देवड़ा, राहुल कुमार खेदड़, प्रवीण कुमार, जसवन्त सिंह, राजेन्द्र सिंह (द्वितीय बार), मुकेश कुमार, धर्मेन्द्र कुमार और रितुदमन सिंह के नाम इस सूची में शामिल हैं।

✦कांस्टेबल, महिला कांस्टेबल एवं चालक

✦पुलिस बल की सबसे मजबूत रीढ़ माने जाने वाले और फील्ड में दिन-रात डटने वाले कांस्टेबलों, महिला कांस्टेबलों व चालकों में शिवराज बैरवा, संतोष चाहर, नरेन्द्र कुमार, लाला राम, सीताराम जांगिड़, पवन लिम्बा (तृतीय बार), अनिल कुमार, मुकेश चन्द, सतीश चन्द, राहुल त्रिवेदी, विश्वेन्द्र सिंह, हेमेन्द्र सिंह, पुखराज, कमलेन्द्र मेहराणा, दीपक कुमार, कृष्ण कुमार यादव, विनोद कुमार, राजकिशोर, विजय कुमार (चालक), सुरेन्द्र, लक्ष्मण चौधरी, गुमान सिंह, दिनेश चन्द, राजेन्द्र प्रसाद, जीतराम चौधरी, विकास कुमार सहारण, सुरेन्द्र कुमार गुर्जर, संदीप कुमार, अनिल कुमार योगी, दयालसिंह, गंगा, महेन्द्र कुमार जाट, नरेश कुमार बैरवा, सुन्दर सिंह, अनिल कुमार, हरि कुमार जाट (द्वितीय बार), सत्यनारायण मीणा, धर्मेन्द्र कुमार मीणा, भूपेन्द्र कुमार नागर, दिपक लबाना, संजू जिजवाड़िया और सुनिता के नाम शामिल हैं।

महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा ने कहा है कि यह सम्मान उत्कृष्ट सेवा, कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा के प्रति समर्पण का प्रतीक है तथा इससे पुलिस बल में बेहतर कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने सभी सम्मानित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को बधाई देते हुए भविष्य में भी इसी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की है।

तंबाकू, नशे का बदलता स्वरूप और आधुनिक दौर की चुनौती

(लेखक-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी)

आजतक राजनीतिक सामाजिक या व्यक्तिगत संगठनों द्वारा तंबाकू व नशीली चीजों के विरुद्ध उग्र आंदोलन क्यों नहीं चलाया यह विचारणीय प्रश्न ?क्या हम एक मूक सामूहिक हत्या के मूकदर्शक बने हुए हैं?

तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2026 मनाने के साथ शासन प्रशासन विद्यालयों, महाविद्यालयों, पंचायतों,नगर निकायों,सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, चिकित्सक समुदाय,मीडिया और राजनीतिक दलों को साथ मिलकर सशक्त राष्ट्रव्यापी उग्र तंबाकू निषेध आंदोलन चलाने की जरूरत?

तंबाकू निषेध नशा मुक्त भारत- अगर भ्रष्टाचार,आरक्षण, नागरिकता, कृषि कानून, क्षेत्रीय पहचान या सामाजिक न्याय के प्रश्न राष्ट्रीय बहस और जनआंदोलन का विषय बन सकते हैं, तो नशा मुक्त संपूर्ण क्रांति आंदोलन क्यों नहीं बना? वैश्विक स्तरपर हर वर्ष 31 मई को पूरी दुनियाँ में वर्ल्ड नों टोबैक्को अर्थात विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। हर वर्ष इस अवसर पर भाषण होते हैं, शपथ ली जाती है, पोस्टर लगाए जाते हैं और तंबाकू के दुष्परिणामों पर चर्चा होती है।लेकिन एक कड़वा प्रश्न आज हमारे सामने खड़ा है,क्या केवल एक दिन का यह प्रतीकात्मक आयोजन उस भयावह महामारी को रोक सकता है जो प्रतिदिन लाखों लोगों के शरीर में कैंसर, हृदय रोग, स्ट्रोक और फेफड़ों की घातक बीमारियों का जहर घोल रही है? भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में नागरिकता कानून,आरक्षण,भ्रष्टाचार,किसानों की समस्याएं,भाषा विवाद, जल-जंगल-जमीन के प्रश्न, मंडल -कमंडल की राजनीति, जनलोकपाल आंदोलन, महिला सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी और क्षेत्रीय अस्मिता जैसे मुद्दे बड़े जनांदोलनों का रूप ले चुके हैं।सड़कों पर लाखों लोग उतरते हैं,संसद और विधान सभाओं में बहस होती है, सरकारें झुकती हैं और नीतियां बदलती हैं।परंतु मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र इस आर्टिकल का माध्यम से शासन प्रशासन व समाज से पूछना चाहता हूं कि तंबाकू, जो हर वर्ष लाखों परिवारों को उजाड़ देता है, आज भी उतना बड़ा राजनीतिक और सामाजिक आंदोलन क्यों नहीं बन पाया? जब किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य तंबाकूजनित कैंसर से मरता है, जब किसी बच्चे का पिता गुटखा या सिगरेट के कारण असमय दुनियाँ छोड़ देता है, जब किसी मां की आंखों के सामने उसका जवान बेटा निकोटीन की लत का शिकार होकर जीवन हार जाता है, तब यह केवल व्यक्तिगत त्रासदी नहीं रह जाती,बल्कि यह राष्ट्रीय चिंता का विषय बन जाती है। मेरे अपने एक निकट संबंधी की मृत्यु भी तंबाकूजनित कैंसर के कारण हुई। ऐसे हजारों-लाखों परिवारों का दर्द यह संकेत देता है कि अब तंबाकू निषेध को केवल स्वास्थ्य अभियान नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप देने की आवश्यकता है।

साथियों बात अगर हम तंबाकू व नशीली चीजों के खिलाफ़ बहुत बड़े आंदोलन की करें तो तंबाकू निषेध आंदोलन को इस तरह के आंदोलन समकक्ष बनाने की जरूरत है जैसे भारतीय लोकतंत्र का इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि जब किसी मुद्दे को जनआंदोलन का रूप मिला, तब उसने सरकारों की नीतियों,कानूनों और सामाजिक व्यवहार को प्रभावित किया। वर्ष 1974 का जेपी आंदोलन (संपूर्ण क्रांति आंदोलन), वर्ष 1990 का मंडल आयोग आरक्षण आंदोलन 1980 और 1990 के दशक का राम जन्मभूमि आंदोलन,वर्ष 2011 का अन्ना हजारे के नेतृत्व वाला भ्रष्टाचार विरोधी जनलोकपाल आंदोलन, वर्ष 2019- 20 का नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) विरोधी आंदोलन, वर्ष 2020-21 का कृषि कानूनों के विरुद्ध किसान आंदोलन, वर्ष 2015 और उसके बाद विभिन्न राज्यों में हुए पटीदार आरक्षण आंदोलन,जाट आरक्षण आंदोलन, मराठा आरक्षण आंदोलन, गुर्जर आरक्षण आंदोलन तथा हाल के वर्षों में विभिन्न राज्यों में जातीय, सामाजिक और क्षेत्रीय पहचान से जुड़े आंदोलनों ने यह सिद्ध किया है कि संगठित जनदबाव लोकतांत्रिक व्यवस्था में परिवर्तन का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।इन आंदोलनों ने न केवल राजनीतिक विमर्श को प्रभावित किया बल्कि सरकारों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए भी बाध्य किया। आज 30 मई 2026 से महाराष्ट्र में शुरू हुआ मनोहर जरॉगे का मराठा आरक्षण आंदोलन सहित देश के अनेक हिस्सों में सामाजिक, जातीय और आरक्षण से जुड़े आंदोलन लगातार सुर्खियों में हैं, जो यह दर्शाते हैं कि जनता जब किसी विषय को अपने अस्तित्व, अधिकार या भविष्य से जोड़ लेती है तो वह एक विशाल जनशक्ति का रूप धारण कर लेता है। तो फिर तंबाकू व नशीली चीजों के विरुद्ध ऐसा आंदोलन किसी राजनीतिक सामाजिक या व्यक्तिगत संगठन में क्यों नहीं उठाया है यह विचारणीय प्रश्न है?

साथियों, पिछले एक दशक में नशे का स्वरूप तेजी से बदला है। कभी बीड़ी, सिगरेट और तंबाकू की पुड़िया तक सीमित रहने वाला यह कारोबार अब अत्याधुनिक तकनीक के आवरण में युवाओं के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ई- सिगरेट, वेप्स, निकोटीन पॉड्स, फ्लेवर्ड हुक्के, निकोटीन पाउच और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक धूम्रपान उपकरण आधुनिक जीवनशैली के प्रतीक के रूप में प्रचारित किए जा रहे हैं। तंबाकू उद्योग ने समझ लिया है कि यदि उसे नई पीढ़ी को अपने जाल में फंसाना है तो उत्पाद का स्वरूप बदलना होगा। इसलिए आज कई वेपिंग उपकरण पेन ड्राइव, स्मार्ट गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन या स्टाइलिश एक्सेसरी जैसे दिखाई देते हैं। किशोर और युवा इन्हें आधुनिकता, स्वतंत्रता और सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक समझने लगते हैं। चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, वनीला, मिंट और अन्य आकर्षक फ्लेवर के माध्यम से निकोटीन को मीठे जहर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है।यह रणनीति केवल व्यापारिकनहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक भी है,क्योंकि स्वाद और आकर्षण के माध्यम से लत को आसान बनाया जाता है।

साथियों, सबसे चिंताजनक बात यह है कि इन आधुनिक उत्पादों को अक्सर पारंपरिक सिगरेट से कम हानिकारक बताने का भ्रम फैलाया जाता है।अनेक युवा यह मान लेते हैं कि वेपिंग सुरक्षित है,जबकि वैज्ञानिक अध्ययनों ने संकेत दिया है कि ई-सिगरेट से निकलने वाला एयरोसोल निकोटीन सहित अनेक हानिकारक रसायनों से भरा होता है। निकोटीन स्वयं अत्यधिक नशे की लत पैदा करने वाला पदार्थ है। इसके अतिरिक्त कई उपकरणों में प्रयुक्त धातुओं, रसायनों और अन्य तत्वों के दीर्घकालिक प्रभाव अभी भी शोध का विषय हैं। इसलिए यह कहना कि आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक धूम्रपान पूरी तरह सुरक्षित है, वैज्ञानिक दृष्टि से उचित नहीं होगा।वास्तव में यह नशे का नया मुखौटा है,जिसका उद्देश्य युवाओं को आकर्षित करना और बाजार का विस्तार करना है।तंबाकू और निकोटीन की इस महामारी का सबसे भयावह पक्ष यह है कि इसका शिकार केवल सेवन करने वाला व्यक्ति ही नहीं होता।पैसिव स्मोकिंग या अप्रत्यक्ष धूम्रपान उन लाखों निर्दोष लोगों की जान ले रहा है जिन्होंने कभी सिगरेट या तंबाकू को हाथ तक नहीं लगाया। घरों, कार्यालयों, रेस्तरां, सार्वजनिक स्थलों और वाहनों में छोड़ा गया धुआं आसपास मौजूद लोगों के शरीर में प्रवेश करता है।बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और कमजोर स्वास्थ्य वाले व्यक्तियों पर इसका प्रभाव और भी गंभीर होता है। जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करता है तो वह केवल अपने स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि दूसरों के स्वास्थ्य अधिकारों का भी उल्लंघन करता है। यही कारण है कि पैसिव स्मोकिंग को केवल व्यक्तिगत व्यवहार का प्रश्न नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उत्तरदायित्व का विषय माना जाता है।

साथियों, कई विशेषज्ञों का मानना है कि पैसिव स्मोकिंग के कारण होने वाली मौतों को केवल दुर्घटना याव्यक्तिगत दुर्भाग्य नहीं कहा जा सकता। यह ऐसी स्थिति है जिसमें निर्दोष लोग दूसरों की आदतों के कारण बीमारी औरमृत्यु का शिकार बनते हैं। धुएं में हजारों प्रकार के रसायन पाए जाते हैं, जिनमें अनेक कैंसरकारी तत्व भी शामिल हैं। यही कारण है कि विश्वभर में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंध संबंधी कानून बनाए गए हैं। लेकिन कानून तभी प्रभावी होते हैं जब उनका कठोर और ईमानदार क्रियान्वयन हो। भारत में भी कई स्थानों पर धूम्रपान निषेध के नियम हैं, परंतु उनका पालन अभी भी चुनौती बना हुआ है।

साथियों, यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तंबाकू विरोधी संघर्ष आज तक एक बड़े जनांदोलन का रूप क्यों नहीं ले पाया। इसका पहला कारण यह है कि तंबाकू तत्काल मृत्यु नहीं देता। सड़क दुर्घटना,हिंसा या प्राकृतिक आपदा की तरह इसका प्रभाव अचानक दिखाई नहीं देता। यह धीरे-धीरे शरीर को भीतर से नष्ट करता है। कैंसर, हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां वर्षों में विकसित होती हैं। इसलिए जनता का आक्रोश कभी एक साथ विस्फोटक रूप में सामने नहीं आता। दूसरा कारण तंबाकू उद्योग का विशाल आर्थिक ढांचा है। खेती, उत्पादन, वितरण और कर राजस्व से जुड़े अनेक हित इसमें शामिल रहते हैं। तीसरा कारण सामाजिक स्वीकृति है। कई लोग तंबाकू सेवन को व्यक्तिगत पसंद का विषय मानते हैं, जबकि इसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। चौथा कारण जागरूकता और क्रियान्वयन के बीच की दूरी है। कानून मौजूद हैं, चेतावनियां मौजूद हैं, लेकिन व्यवहार परिवर्तन अपेक्षित स्तर पर नहीं हो पाया है।

साथियों, भारत में तंबाकू और अन्य नशे के नियंत्रण की जिम्मेदारी केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं है।इसमेंपुलिस विभाग, राज्य आबकारी विभाग,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, नारकोटिक्स नियंत्रण एजेंसियां, स्थानीय निकाय, जिला प्रशासन और विभिन्न नियामक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस प्रकार अवैध शराब से मौतों के मामलों में कई राज्यों में संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती रही है, उसी प्रकार तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी पालन को लेकर भी जवाबदेही तय करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। जब किसी क्षेत्र में खुलेआम प्रतिबंधित उत्पाद बिकते हैं,जब स्कूलों के आसपास तंबाकू की बिक्री होती है या जब सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान रोकने के नियम लागू नहीं होते, तब केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। प्रभावी निगरानी, नियमित निरीक्षण, जनभागीदारी और उत्तरदायित्व की स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक है। साथियों, आज की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि नई पीढ़ी नशे को आधुनिकता और स्टेटस सिंबल के रूप में देखने लगी है। सोशल मीडिया,फिल्मों, डिजिटल संस्कृति और समूह दबाव के कारण कई किशोर यह मान बैठते हैं कि वेपिंग या धूम्रपान उन्हें अधिक आकर्षक, परिपक्व या आधुनिक बनाता है।वास्तविकता इसके ठीक विपरीत है। चिकित्सा विज्ञान यह संकेत देता है कि निकोटीन की लत मस्तिष्क के विकास को प्रभावित कर सकती है, विशेषकर किशोरावस्था में। कुछ मामलों में ई-सिगरेट से जुड़ी गंभीर फेफड़ों की बीमारियों की भी रिपोर्ट सामने आई हैं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशेष चिकित्सीय श्रेणियों में अध्ययन किया गया है। यह स्पष्ट है कि आधुनिक नशे का आकर्षक आवरण उसके भीतर छिपे जोखिमों को समाप्त नहीं करता।इसलिए अब आवश्यकता केवल जागरूकता की नहीं बल्कि सामाजिक चेतना के व्यापक पुनर्जागरण की है। स्कूलों और कॉलेजों में नशा विरोधी शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाया जाना चाहिए।

संपादकीय

जन के हित के हेत

भले ही हिंदी पत्रकारिता गफलत में अपनी पहली शताब्दी न मना सकी हो, लेकिन वह द्विशताब्दी के मौके पर खासी उत्साहित है। वह आत्ममंथन के दौर से गुजर रही है। आज से दो सौ साल पहले उत्तर भारत से जाकर तत्कालीन कलकत्ता को कर्मभूमि बनाने वाले पं. युगल किशोर शुक्ल ने 'उदन्त मार्तण्ड' के रूप में हिंदी पत्रकारिता का बीजारोपण किया था। भले ही वह पत्र आर्थिक झंझावातों से अधिक समय तक न चल सका, लेकिन अपनी 'आदि प्रतिज्ञा' से वह जो पत्रकारिता का लक्ष्य तय कर गया, वह आज भी उतना ही जरूरी व प्रासंगिक है। 'उदन्त मार्तण्ड' के प्रवेशांक में पं. शुक्ल ने लिखा था कि इस समाचार पत्र का प्रकाशन- 'हिंदुस्तानियों के हित के हेत' .. किया जा रहा है। निस्संदेह, ध्येय वाक्य के गहरे निहितार्थ थे और आज भी हैं। सही मायने में पत्र ने दो सदी पहले पत्रकारों को उनका 'कर्मपथ' बता दिया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जबकि यह हिंदी भाषा का समाचार पत्र था, लेकिन उसकी फिक्र केवल हिंदी भाषियों की ही नहीं थी। उसकी 'आदि प्रतिज्ञा' समस्त हिंदुस्तानी समाज के हित को लेकर थी। पत्र का नाम 'उदन्त मार्तण्ड' यानी उगता सूरज था। बाकायदा समाचार पत्र के नाम के साथ संस्कृत में लिखा होता था कि जैसे सूरज के प्रकाश के बिना अंधेरा दूर नहीं होता, उसी तरह अज्ञ जन समाचार पत्र के बिना ज्ञानवान नहीं बन सकते। यह भी कि ज्ञान के प्रकाश को फैलाने के मकसद से इस समाचार पत्र का प्रकाशन किया जा रहा है। निश्चय ही उदन्त मार्तड की 'आदि प्रतिज्ञा और ध्येय' में सभी भाषाओं की पत्रकारिता का लक्ष्य आज भी यही है। निश्चय ही यह पत्रकारिता बिरादरी को आईना दिखाता है कि हमारी पत्रकारिता हर हिंदुस्तानी के हित के हेत है? क्या हम हम समाज में अज्ञ को ज्ञानवान बनाने का काम कर रहे हैं? क्या हमारे शब्द उतने ही अर्थवान व सारवान हैं, जितना इस पेशे से अपेक्षित है। निश्चय ही यह अवसर पत्रकारिता बिरादरी को आत्ममंथन का मौका देता है। हिंदी पत्रकारिता के प्रतीक पुरुष स्व. प्रभाष जोशी ने एक बार पत्रकारिता के छात्रों से बातचीत करते हुए कहा था कि पत्रकारिता 'ऋषिकर्म' है। जिसमें घर फूंक तमाशा देखने का जज्बा हो, वही पत्रकारिता में आए। पैसे कमाने के लिये तमाम पेशे हैं। साथ ही यह भी कि किसी डेढ़ पेज की प्रेस विज्ञप्ति में यदि कोई डेढ़ लाइन की खबर निकाल सके, तो वही असली पत्रकार है। बाकी सब विज्ञापन है। लेकिन विडंबना यह है कि आज विश्वविद्यालयों से निकलने वाले पत्रकारिता के छात्रों में बिरले ही ऐसे होते हैं, जो वेतन, पैकेज व पद के सम्मोहन से मुक्त होकर मिशनरी पत्रकारिता का जज्बा रखते हों। आज पत्रकारिता के नवसाक्षरों की बड़ी फौज पत्रकारिता के ग्लैमर व प्रसिद्धि के प्रलोभन में इस पेशे में आती है। उसे आजादी की लड़ाई में सर्वस्व अर्पित करने वाले 'स्वराज' अखबार का शायद ही भान हो, जिसके ढाई वर्ष के अल्पकाल में संपादकों को डेढ़ सौ साल की सजाएं हुई। लेकिन उसके बावजूद संपादक पद के लिये विज्ञापन देने पर जज्बे के पत्रकारों की लाइन लग जाती थी। निश्चित रूप से पत्रकारिता जीवन मूल्यों की शुचिता व सामाजिक दायित्वों का पेशा है। यह विशुद्ध कारोबार या व्यवसाय नहीं हो सकता है। विडंबना यह है कि तकनीकी क्रांति के बाद जब से बड़ी पूंजी की समाचारों के प्रकाशन में दखल बढ़ी है, तब से संपादक नामक संस्था क्षीण हुई है और पूंजीपति की दखल में वृद्धि हुई है। पिछली सदी में एक दिग्गज संपादक की वह टिप्पणी आज भी प्रासंगिक है कि 'भविष्य के अखबार रूप-रंग व प्रकाशन में तो आकर्षक होंगे, लेकिन उनमें पत्रकारिता की आत्मा न होगी।'

निकोटीन का नया जालः युवाओं की नसों में घुलता जहर

(लेखक- योगेश कुमार गोयल)

- युवाओं के भविष्य पर मंडराता तंबाकू का संकट

(विश्व तम्बाकू निषेध दिवस (31 मई) पर विशेष)

तंबाकू मानव स्वास्थ्य का ऐसा मौन शत्रु है, जिसकी विनाशकारी शक्ति को लेकर अब किसी प्रकार का संशय शेष नहीं रह गया है। पिछले कई दशकों में विश्वभर में हुए हजारों वैज्ञानिक अध्ययनों ने यह निर्विवाद रूप से सिद्ध किया है कि धूम्रपान अथवा किसी भी रूप में तंबाकू का सेवन शरीर के लिए घातक है। इसके बावजूद जब कम उम्र के किशोरों और युवाओं को सिगरेट, बीड़ी, ई-सिगरेट, गुटखा, पान मसाला अथवा अन्य तंबाकू उत्पादों का सेवन करते देखा जाता है तो यह केवल स्वास्थ्य का नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक चेतना का भी गंभीर संकट प्रतीत होता है। वास्तव में किशोरों के मन में तंबाकू को लेकर अनेक भ्रम घर कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि धूम्रपान से तनाव कम होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, व्यक्तित्व आकर्षक बनता है, मन शांत रहता है या फिर यह आधुनिकता और परिपक्वता का प्रतीक है। विज्ञापनों, फिल्मों, सोशल मीडिया और मित्र समूहों के प्रभाव से यह भ्रम और भी गहरा हो जाता है जबकि वैज्ञानिक सत्य इससे बिल्कुल विपरीत है। तंबाकू न तो शक्ति देता है, न व्यक्तित्व निखारता है और न ही तनाव का स्थायी समाधान है। सच्चाई यह है कि तंबाकू एक धीमा जहर है, जो शरीर के भीतर चुपचाप अपना विनाशकारी प्रभाव छोड़ता रहता है। यह कैंसर, हृदय रोग, फेफड़ों की बीमारियों, स्ट्रोक और अनेक घातक रोगों को जन्म देकर व्यक्ति को धीरे-धीरे मृत्यु की ओर धकेलता है। इसलिए तंबाकू के विरुद्ध जागरूकता आज केवल स्वास्थ्य नही बल्कि भावी पीढ़ियों के अस्तित्व की लड़ाई बन चुकी है।

लोगों को तंबाकू को छोड़ने और इसे कभी हाथ नहीं लगाने के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से ही प्रतिवर्ष विश्वभर में 31 मई को 'विश्व तम्बाकू निषेध दिवस' मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य तम्बाकू सेवन के व्यापक प्रसार और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों की ओर ध्यान आकर्षित करना है, जो दुनियाभर में प्रतिवर्ष लाखों मौतों का कारण बनता है। इस वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस 'आकर्षण का पर्दाफाश- निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला करना' थीम के साथ मनाया जा रहा है। यह थीम निर्धारित करते समय तंबाकू उद्योग द्वारा युवाओं को टारगेट करते हुए बनाए गए मार्केटिंग के तरीकों की चिंता बढ़ाने वाली प्रवृत्ति की ओर खास ध्यान दिया गया है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार सोशल मीडिया और लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म इत्यादि के जरिये दुनियाभर में युवा तेजी से तंबाकू उत्पादों के आकर्षण और संपर्क में आ रहे हैं, जो उनके स्वास्थ्य और समाज कल्याण के लिए एक बड़ा खतरा है। दुनियाभर के सर्वेक्षण लगातार दिखा रहे हैं कि अधिकांश देशों में 13-15 वर्ष की आयु के बच्चे तंबाकू और निकोटीन उत्पादों का इस्तेमाल कर रहे हैं।

वैसे तो हुक्का, गुटखा, खैनी, जर्दा इत्यादि तमाम तंबाकू उत्पाद स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं लेकिन इसका सबसे हानिकारक रूप है धूम्रपान, जो हर साल लाखों लोगों की मौत का कारण बनता है। धूम्रपान करने वालों द्वारा सालभर में सात हजार करोड़ से ज्यादा सिगरेटें फूंक दी जाती हैं। हर साल फूंकी जाने वाली इन्हीं सिगरेटों के धुएं से वातावरण भी कितना प्रदूषित होता है, इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि इस खतरनाक धुएं से करीब 50 टन तांबा, 15 टन शीशा, 11 टन कैडमियम तथा कई अन्य खतरनाक रसायन वातावरण में घुलते हैं। हालांकि सिगरेटें महंगी होने के कारण भारत में बीड़ी का प्रचलन निम्न तथा मध्यमवर्गीय तबके में ज्यादा है और ऐसा अनुमान है कि देश में प्रतिवर्ष सौ अरब रुपये मूल्य से भी अधिक की बीड़ियों का सेवन किया जाता है। एक सरकारी अध्ययन के मुताबिक तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के इलाज पर सालभर में करीब 1.04 लाख करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। तीन दशक पूर्व प्रकाशित अपनी पुरस्कृत पुस्तक 'मौत को खुला निमंत्रण' में मैंने विस्तार से यह बताया है कि धूम्रपान वास्तव में एक ऐसा धीमा जहर है, जो हमारे शरीर में धीरे-धीरे प्राणघातक रोगों को जन्म देता है और व्यक्ति को धीमी गति से मृत्यु शैया पर पहुंचा देता है।

दुनियाभर में धूम्रपान के कारण 2019 में 77 लाख लोगों की मौत हुई, जिनमें से 17 लाख मौतें इस्केमिक हार्ट डिजीज के कारण, 16 लाख सीपीओडी के कारण, 13 लाख ट्रैकियल, ब्रोंकस और फेफड़ों के कैंसर से तथा 10 लाख स्ट्रोक के कारण हुई। रिपोर्ट के मुताबिक दुनियाभर में होने वाली मौतों में से हर 5 में से 1 पुरूष की मौत धूम्रपान के कारण हो रही है। विभिन्न सर्वेक्षणों के अनुसार माना गया है कि विकसित देशों में चालीस फीसदी से ज्यादा पुरूष और इक्कीस फीसदी से ज्यादा स्त्रियां धूम्रपान करती हैं जबकि विकासशील देशों में सिर्फ आठ फीसदी स्त्रियों को इसकी लत लगी है तथा पुरूषों की संख्या पचास फीसदी से अधिक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तम्बाकू के सेवन के कारण प्रतिदिन करीब आठ हजार व्यक्ति फेफड़ों के कैंसर के शिकार होकर मर जाते हैं। संगठन का अनुमान है कि यदि दुनियाभर में धूम्रपान की लत ऐसे ही बढ़ती रही तो बहुत जल्द धूम्रपान के कारण पचास करोड़ लोग मारे जा चुके होंगे और अगले तीस वर्षों में केवल गरीब देशों में ही धूम्रपान से मरने वालों की संख्या दस लाख से बढ़कर सत्तर लाख तक पहुंच जाएगी। संगठन का अनुमान है कि प्रतिवर्ष विश्वभर में आठ हजार से ज्यादा नवजात शिशु धूम्रपान की वजह से असमय काल के ग्रास बन जाते हैं। आंकड़ों से पता चलता है कि सभी प्रकार के कैंसर में से करीब 40 फीसदी का कारण धूम्रपान ही होता है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि कैंसर, हृदय रोग, सांस की बीमारी, डायबिटीज इत्यादि बीमारियों में भी धूम्रपान काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को धूम्रपान से बचना चाहिए।

बहरहाल, धूम्रपान छोड़ने के फायदों के बारे में विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहना है कि धूम्रपान छोड़ने के सिर्फ बीस मिनट के अंदर उच्च रक्तचाप में गिरावट आती है तथा बारह घंटे के बाद रक्त में कार्बन मोनोक्साइड के विषैले कणों का स्तर सामान्य हो जाता है। दो से बारह सप्ताह में फेफड़ों की कार्यक्षमता में तेजी से वृद्धि होती है तथा एक से नौ माह में खांसी तथा श्वसन संबंधी समस्याएं कम हो जाती हैं। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक मनुष्य के फेफड़ों में जादुई क्षमता होती है, जो धूम्रपान से होने वाले कुछ नुकसान को स्वयं ठीक कर देती है और जो व्यक्ति धूम्रपान छोड़ देते हैं, उनकी चालीस फीसदी कोशिकाएं ऐसे लोगों की तरह ही हो जाती हैं, जिन्होंने कभी धूम्रपान नहीं किया।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं तथा 33 वर्ष पूर्व नशे के दुष्प्रभावों पर 'मौत को खुला निमंत्रण' पुस्तक लिख चुके हैं)

धर्म का अर्थ

किसी संत के पास एक युवक आया और उसने उनसे धर्म ज्ञान देने की प्रार्थना की। संत ने कहा कि वह उनके साथ कुछ दिन रहे, फिर वे उसे धर्म का सार बताएंगे। युवक उनके आश्रम में रहने लगा। वह संत की हर बात मानता और उनकी सेवा करता। इस तरह कई दिन बीत गए। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संत उसे धर्म के बारे में कब बताएंगे। वह उनसे धर्म की चर्चा करने के लिए उत्सुक था।

वह चाहता था कि उनसे शिक्षा प्राप्त कर घर लौट जाए पर संत कुछ खास कह ही नहीं रहे थे। युवक का धैर्य जवाब दे रहा था। एक दिन उसने पूछ ही दिया-मुझे आए इतने दिन हो गए पर अब तक आपने मुझे धर्म का सार नहीं बताया। आखिर मैं कब तक प्रतीक्षा करूं? संत ने हंसकर कहा- कैसी बात कर रहे हो। तुम जिस दिन से मेरे साथ रह रहे हो उस दिन से मैं तुम्हें धर्म का सार बता रहा हूं। पर तुम ध्यान ही नहीं दे रहे। युवक ने चौंककर कहा-वो कैसे?

संत बोले- जब तुम मेरे लिए पानी लाते हो, मैं उसे सदैव प्रेम से स्वीकार करता हूं। तुम्हारे प्रति आभार भी प्रकट करता हूं। जब-जब तुमने मुझे आदरपूर्वक प्रणाम किया, मैंने तुम्हारे साथ नम्रता का व्यवहार किया। यही तो धर्म है जो हमारे दैनंदिन व्यवहार में झलकता है। धर्म कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। तुम मेरे और कार्यों पर गौर करो। मैं लोगों से कैसे मिलता हूं और किस तरह उनकी सहायता करता हूं। इससे अलग कुछ भी धर्म नहीं है। युवक संत का आशय समझ गया।

विचार मंथन

नीट परीक्षा में सेना की सहायता : सरकार की असफलता?

(लेखक- सनत जैन)

देश की सबसे बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल नीट को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है। पिछले तीन वर्षों से नीट परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने की बात सामने आती रही है। इसमें लाखों परीक्षार्थी शामिल होते हैं। परीक्षा केंद्रों पर अनियमितताएँ और लाखों छात्रों के भविष्य पर मंडराते संकट के बीच अब सरकार सेना और वायुसेना की सहायता लेने की खबर आई है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और नीट परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन और निगरानी के लिए सरकार सैन्य संसाधनों का उपयोग करने जा रही है। इसके पहले कभी भी सेना का उपयोग इस तरह से नहीं हुआ है। पिछले 75 वर्षों के इतिहास में जब कानून व्यवस्था की स्थिति में बहुत जरूरत होने पर ही सेना को कुछ समय के लिए तैनात किया जाता है। पहली बार परीक्षा मे सेना और वायु सेना का उपयोग होने की बात सामने आ रही है। यह निर्णय दो तरह के प्रश्न खड़े करता है। पहला, क्या सरकार की नीट की परीक्षा के प्रश्न पत्र बार-बार लीक हो रहे हैं, उसकी गंभीरता और समस्या से निपटने के लिए लिया गया है? दूसरा, क्या यह सरकार ने मान लिया है संबंधित मंत्रालय और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था, प्रशासन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल है? सरकार और उसके समर्थकों का तर्क है, लाखों परीक्षार्थियों के भविष्य की रक्षा के लिए सेना की मदद ली जा रही है, इसमें गलत क्या है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा मंडल के परीक्षा परिणाम को लेकर भी लाखों छात्रों का भविष्य अंधकार में हो गया है। सरकार शायद इस बात से घबरा गई है कि नीट पेपर लीक और सीबीएसई परीक्षा परिणाम को लेकर लाखों छात्र सड़क पर उतरकर अपना विरोध जाता रहे हैं। इस विरोध को दबाने के लिए तथा परीक्षार्थियों का विश्वास बना रहे। हाल के वर्षों में पेपर लीक और संगठित नकल गिरोहों ने परीक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता को लगभग समाप्त कर दिया है। इस स्थिति में छात्रों और युवाओं के विरोध को नियंत्रित करने के लिए सरकार सेना की विश्वसनीयता का सहारा लेकर इस विवाद को शांत करने की कोशिश कर रही है। छात्रों और अभिभावकों का मानना है, परीक्षा आयोजित करने की जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होने के कारण तथा प्रवेश परीक्षाओं के माध्यम से चयनित कर करोड़ों रुपए की कमाई करने का यह नया धंधा शुरू हो गया है और यह सरकार की मिलीभगत से ही संभव हो पा रहा है। इसलिए छात्रों और अभिभावकों में भारी गुस्सा देखने को मिल रहा है। दूसरी ओर यह सवाल भी उठने लगा है कि जब परीक्षा तक सरकार नहीं करा पा रही है, और दावे किए जा रही, अब इसको लेकर सरकार की आलोचना बड़े पैमाने पर शुरू हो गई है। सेना का काम सीमाओं की सुरक्षा करना है। नाकि प्रश्नपत्रों की ढुलाई करना तथा पेपर लीक होने से रोकना है। देश की सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा कराने वाली संस्थाएँ इतनी कमजोर हैं अथवा वह भ्रष्ट हो चुकी हैं। परीक्षा संचालन के लिए सैन्य सहायता, प्रशासनिक असफलता का सबसे बड़ा प्रतीक भी माना जा रहा है। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसे फ़गवर्नेंस फेल्योरफ़ तथा भ्रष्ट व्यवस्था निरूपित किया है।

असल समस्या केवल प्रश्नपत्र लीक की नहीं है। पूरी परीक्षा प्रणाली भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। नीट परीक्षा के माध्यम से हर साल कोचिंग सेंटर और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था द्वारा करोड़ों रुपए कि भ्रष्टाचार और मिलीभगत के कई कहानियां सामने आ चुकी है। जिसमें चयन के लिए लाखों रुपए लेकर एम्स और सरकारी अस्पतालों में प्रवेश दिया गया है। इसी तरह से अन्य परीक्षाओं में भी लाखों करोड़ों रुपए लेकर उन लोगों का चयन किया जाता है जो पैसा देने में सक्षम होते हैं। इस काम में राजनीतिक हस्तक्षेप तथा जिन लोगों को यह काम सोपा गया है उन्हें प्राथमिकता और साक्षमता के अनुसार काम न देकर ऐसे लोगों को जिम्मेदारी दी गई है जो इस भ्रष्ट तंत्र को संरक्षित करने का काम करते हैं। नेशनल टेस्ट एजेंसी की स्थापना पारदर्शी और तकनीकी रूप से सक्षम परीक्षा प्रणाली के लिए की गई थी। पिछले वर्षों में लगातार विवादों और लाखों रुपए की अवैध वसूली से नेशनल टेस्ट एजेंसी की साख को भारी नुकसान हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है, केंद्रीकृत परीक्षा व्यवस्था, कमजोर निगरानी, निजी एजेंसियों पर निर्भरता कोचिंग संस्थाओं के साथ मिली भगत और जवाबदेही तय नहीं होने से यह संकट इतना बढ़ गया है। सरकार को सेना की सहायता लेकर अपना विश्वास आम जनता के बीच में बनाना पड़ रहा है। इस पूरे विवाद का सबसे दुखद पहलू यह है, इसका बोझ छात्रों पर पड़ रहा है। दक्षिण के राज्य लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। नीट परीक्षा में केंद्रीयकृत भ्रष्टाचार होने का आरोप लगने लगा है। लाखों युवा वर्षों तक तैयारी करते हैं। परिवार कर्ज लेते हैं। मानसिक तनाव झेलते हैं। अंत में परीक्षा में गड़बड़ी कर अयोग्य छात्रों का प्रवेश सरकारी मेडिकल कॉलेज और एम्स में हो जाता है। यहां पर नाम मात्र की फीस लगती है। निजी मेडिकल कॉलेज की लाखों रुपए प्रतिवर्ष की फीस होती है। जिसके कारण नीट परीक्षा में हर साल करोड़ों रुपए के अवैध लेनदेन का आरोप लगने लगा है। यह केवल एक परीक्षा का संकट नहीं, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर आमजनों में रोष देखने को मिल रहा है। सरकार यदि सेना की सहायता लेकर परीक्षा को सुरक्षित कराने में सफल भी हो जाती है, तब भी यह स्थायी समाधान नहीं है।

सरकारी तेल कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी बैकअप रखने का आदेश

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और होर्मुज में फंसे जहाज भी चुनौती

नई दिल्ली।

पश्चिम एशिया में गहराते तनाव के मद्देनजर भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने में जुट गया है। केंद्र सरकार ने सरकारी तेल कंपनियों को आपात स्थिति से निपटने के लिए कम से कम 30 दिनों का एलपीजी रिजर्व स्टॉक तैयार रखने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कच्चे तेल का अतिरिक्त भंडार बनाने पर भी काम जारी है, ताकि किसी भी संकटकाल में देश में गैस या ईंधन की किल्लत न हो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा जारी इस निर्देश का उद्देश्य देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं; फरवरी के 69.01 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर मई में यह 106.83 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई हैं। इस भारी उछाल से भारतीय तेल कंपनियों को प्रतिदिन लगभग 550 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जिसका सीधा परिणाम पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल में करीब 7.5 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि के रूप में सामने आया है। वर्तमान में भारत की दैनिक एलपीजी मांग लगभग 72,000 मीट्रिक टन है, जबकि घरेलू रिफाइनरियां प्रतिदिन 52,000 मीट्रिक टन का उत्पादन कर रही हैं। शेष आवश्यकता को पूरा करने के लिए रिफाइनरियों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के प्रयास जारी हैं। उधर, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ते तनाव ने भी चिंता बढ़ा दी है, जहाँ भारत के 13 जहाज, जिनमें 1 एलपीजी कैरियर और 5 कच्चे तेल के जहाज शामिल हैं, फंसे हुए हैं। पोत परिवहन मंत्रालय इन जहाजों की सुरक्षित वापसी पर लगातार नजर बनाए हुए है।

युद्ध के डर से बढ़ी उर्वरक बिक्री, बढ़ी आयात लागत

देश में यूरिया 10 फीसदी और डीएपी की बिक्री 39 फीसदी तक बढ़ी

नई दिल्ली।

पश्चिम एशिया में युद्ध छिड़ने के बाद से भारतीय किसानों में उर्वरक की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं, जिसके चलते देश में यूरिया और डाई अमोनिया फॉस्फेट (डीएपी) की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। खरीफ सम्मेलन में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, किसानों द्वारा घबराहट में की गई खरीद, अत्यधिक भंडारण और जमाखोरी के कारण मार्च से मई के बीच यूरिया की बिक्री में लगभग 10 फीसदी और डीएपी की बिक्री में लगभग 39 फीसदी का उछाल आया है। इसके साथ ही, युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर उर्वरक आयात की लागत में भी भारी वृद्धि हुई है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि युद्ध के बाद से यूरिया की दैनिक बिक्री सामान्य 40,000-45,000 टन से दोगुनी होकर लगभग 80,000-85,000 टन हो गई है। 1 मार्च से 25 मई के बीच उपभोक्ताओं ने कुल 50.5 लाख टन यूरिया और 12.4 लाख टन डीएपी खरीदी, जो पिछले साल की इसी अवधि से क्रमशः 4.5 लाख टन और 3.5 लाख टन अधिक है। मुख्य रूप से महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में यह अतिरिक्त खरीद देखी गई है। सरकार ने ऐसे 100 जिलों की पहचान की है जहां उर्वरक की बिक्री सामान्य से बहुत अधिक हुई है, जिन पर नजर रखी जा रही है। युद्ध ने उर्वरक लागत को भी बढ़ा दिया है। खाद कारखानों के लिए गैस की खरीद 70-80 प्रतिशत महंगी हुई है, जबकि 25 लाख टन आयातित यूरिया 112 प्रतिशत और 13.5 लाख टन आयातित डीएपी 38 प्रतिशत महंगा है। हालांकि, केंद्र सरकार ने बेहतर भंडारण के कदम उठाए हैं, जिससे खरीफ सीजन के लिए आवश्यक 390 लाख टन उर्वरक के मुकाबले देश में 200 लाख टन से अधिक का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है।

आरबीआई की विदेशी मुद्रा आय में रिकॉर्ड उछाल, पहुंचा 1.69 लाख करोड़

नई दिल्ली ।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने वित्त वर्ष 2025-26 में विदेशी मुद्रा लेनदेन से अपनी आय में जबरदस्त वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में करीब 52 प्रतिशत बढ़कर 1.69 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।यह केंद्रीय बैंक के वित्तीय स्वास्थ्य में उल्लेखनीय सुधार का संकेत है। केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में विदेशी मुद्रा लेनदेन से आरबीआई की आय 1.11 लाख करोड़ रुपये थी, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 में बड़ा उछाल देखा गया। इस अवधि में, आरबीआई का कुल बहीखाता आकार भी 15.72 लाख करोड़ रुपये बढ़कर रिकॉर्ड 91.97 लाख करोड़ रुपये हो गया। संपत्ति पक्ष पर यह वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू निवेश (44.9त), स्वर्ण भंडार (63.8 फीसदी) और विदेशी निवेश (7.9 फीसदी) में हुई

बढ़ोतरी के कारण दर्ज की गई। आरबीआई का अधिशेष (सरप्लस) भी वित्त वर्ष 2025-26 में 6.7 प्रतिशत बढ़कर 2,86,588.46 करोड़ रुपये हो गया।

जो पिछले वित्त वर्ष 2,68,590.07 करोड़ रुपये था। यह मजबूत वित्तीय प्रदर्शन देश की आर्थिक स्थिरता में आरबीआई की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

सोना एक हफ्ते में हजार और चांदी दो हजार रुपए से अधिक सस्ती

सोना 1,56,463 रुपए प्रति 10 ग्राम, चांदी 2,63,350 रुपए प्रति किलोग्राम

नई दिल्ली ।

सोने और चांदी के दामों में इस हफ्ते उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के आंकड़ों के अनुसार सोना 1200 रुपए से अधिक और चांदी 2600 रुपए से अधिक सस्ते हुए हैं। इस गिरावट के पीछे वैश्विक अस्थिरता और महंगाई बढ़ने की आशंकाएं मुख्य वजह मानी जा रही हैं, जिससे खरीदारों के लिए यह एक अच्छा मौका बन गया है। इस हफ्ते 24 कैरेट सोने का दाम 1,257 रुपए कम होकर 1,56,463 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया, जो पहले 1,58,720 रुपए था। वहीं चांदी की कीमत में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है, यह 2,650 रुपए सस्ती होकर 2,63,350 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। विभिन्न कैरेट के सोने में भी नरमी आई है, 22 कैरेट सोना अब 1,43,320 और 18 कैरेट सोना 1,17,347 रुपए प्रति 10 ग्राम पर उपलब्ध है।

आईआईएफसीएल का 2025-26 में मुनाफा घटकर 1,379 करोड़ हुआ

नई दिल्ली ।

सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने वित्त वर्ष 2025-26 में अपने मुनाफे में 57 प्रतिशत की बड़ी गिरावट दर्ज की है, जो 1,379 करोड़ रुपए रहा। हालांकि, कंपनी ने इसी अवधि में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए रिकॉर्ड-तोड़ स्वीकृतियां और वितरण कर देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका को बनाए रखा है। वित्त वर्ष 2024-25 में 2,165 करोड़ रुपए के मुनाफे की तुलना में आईआईएफसीएल का लाभ उल्लेखनीय रूप से गिरा है। इसके बावजूद, कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 57,680 करोड़ रुपए की अब तक की सर्वाधिक मंजूरी दी, जो पिछले वित्त वर्ष से लगभग 13 प्रतिशत अधिक है। आईआईएफसीएल के एक वे रिष्ठ अे धिकारी ने बताया कि इस अवधि में वितरण भी 16 प्रतिशत बढ़कर 32,972 करोड़ रुपए हो गया, जिससे देश में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण को मजबूत गति मिली। 31 मार्च 2026 तक, आईआईएफसीएल का एकल आधार ऋण पोर्टफोलियो लगभग 17 प्रतिशत बढ़कर 81,715 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कंपनी की बढ़ती पहुंच और बुनियादी ढांचे के विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, भले ही उसके लाभ में कमी आई हो।

शेयर बाजार ने रिकॉर्ड उछाल से जोरदार गिरावट तक का तय किया सफर

सोमवार को 1000 अ धिक अंकों की रिकॉर्ड तेजी, सप्ताह के आ खिर में सेंसेक्स 76,488 पर बंद

मुंबई।

बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को एक अप्रत्याशित यात्रा का अनुभव हुआ, जो एक मजबूत शुरुआत के साथ शुरू होकर भारी गिरावट के साथ समाप्त हुई। सप्ताह की शुरुआत सोमवार को वैश्विक बाजारों से मिले मजबूत संकेतों, अमेरिका-ईरान वार्ता की उम्मीदों और कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते शानदार तेजी के साथ हुई थी। हालांकि, यह उत्साह अल्पकालिक साबित हुआ, क्योंकि भू-राजनीतिक तनावों ने बाजार का रुख पूरी तरह बदल दिया। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को भारतीय शेयर बाजार ने रिकॉर्ड तोड़ मजबूती दर्ज की। सेंसेक्स 1,073.61 अंक उछलकर 76,488.96 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 312.40 अंक बढ़कर 24,031.70 पर पहुंच गया। बैंकिंग और ऑटो जैसे प्रमुख क्षेत्रों में खरीदारी ने इस तेजी को बल दिया, वहीं रुपये ने भी डॉलर के मुकाबले 35 पैसे की मजबूती दर्ज की। वैश्विक स्तर पर अमेरिका-ईरान वार्ता की उम्मीदें और कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट इसका मुख्य कारण बनीं। हालांकि, यह सकारात्मक माहौल मंगलवार से बिगड़ना शुरू हो गया। वैश्विक भू-राजनीतिक तनावों और विशेष रूप से ईरान पर अमेरिकी हमलों के प्रभावों की आशंकाओं ने निवेशकों को सतर्क कर दिया। मंगलवार को सेंसेक्स 479.26 अंक और निफ्टी 118.00 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। बुधवार को भी बाजार उतार-चढ़ाव भरा रहा और मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ,

सेंसेक्स 141.90 अंक और निफ्टी 6.55 अंक नीचे आए। गुरुवार को ईद के त्योहार के अवसर पर शेयर बाजार बंद रहा। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार की सुबह बाजार में थोड़ी हरियाली दिखी, लेकिन यह ज्यादा देर टिक नहीं पाई। दिन भर हुई भारी बिकवाली के चलते बाजार में तेज गिरावट दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स 1,092.06 अंक टूटकर 74,775.74 पर बंद हुआ, जबकि एनएसई निफ्टी 359.41 अंक गिरकर 23,547.75 के स्तर पर आ गया। इस गिरावट के साथ निफ्टी ने 23,600 और 23,550 जैसे महत्वपूर्ण स्तरों को भी तोड़ दिया, जिससे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुल मिलाकर, भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं ने भारतीय बाजार के एक मजबूत सप्ताह की शुरुआत को भारी गिरावट में बदल दिया।

इंडिगो को 2,537 करोड़ का घाटा, विदेशी मुद्रा, ईंधन व युद्ध ने बढ़ाई मुश्किल

नई दिल्ली।

प्रमुख विमानन कंपनी इंडिगो ने वित्त वर्ष 2026 की चौथी तिमाही में 2,536.9 करोड़ रुपए का समेकित घाटा दर्ज किया है। कंपनी ने इस घाटे के लिए विदेशी मुद्रा में हुए भारी नुकसान, विमानन ईंधन (एटीएफ) की बढ़ी हुई कीमतों और पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उड़ानों के रद्द होने को मुख्य वजह बताया है। पिछले वर्ष की इसी तिमाही में एयरलाइन ने 3,067.5 करोड़ रुपए का लाभ कमाया था। एयरलाइन के अनुसार चौथी तिमाही में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये में लगभग 5 फीसदी की कमजोरी आई, जिससे उसे 4,820 करोड़ रुपए का भारी विदेशी मुद्रा घाटा हुआ। मुख्य वित्तीय अधिकारी गौरव नेगी ने स्पष्ट किया कि यह मुख्य रूप से मार्क-टू-मार्केट नुकसान है, जो विमानों की लीज और रखरखाव से संबंधित भविष्य की देनदारियों से जुड़ा है। इसके अलावा पश्चिम एशिया युद्ध के कारण एयरलाइन को अंतरराष्ट्रीय उड़ानों (लगभग 160 दैनिक उड़ानें) को रद्द करना पड़ा, जिससे परिचालन पर नकारात्मक असर पड़ा। विमानन ईंधन (एटीएफ) की कीमतों में

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 50 फीसदी और घरेलू स्तर पर 25-30 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई, जिसका पूरा बोझ इंडिगो यात्रियों पर नहीं डाल सकी। कुल मिलाकर, तिमाही में इंडिगो का कुल खर्च 30.1 फीसदी बढ़कर 25,932.5 करोड़ रुपए हो गया, जबकि कुल आय केवल 3.2 फीसदी बढ़कर 23,830.7 करोड़ रुपए रही।

निर्यातकों को अब 'ट्रेड कनेक्ट' पर मिलेंगे डिजिटल मूल प्रमाण पत्र

1 जून 2026 से प्रभावी होगी व्यवस्था

नई दिल्ली ।

भारत और ओमान के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (सीईपीए) के तहत निर्यात करने वाले भारतीय निर्यातकों के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा शुरू की जा रही है। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने घोषणा की है कि 1 जून 2026 से निर्यात के लिए आवश्यक 'मूलस्थान का तरजीही प्रमाणपत्र' 'ट्रेड कनेक्ट' नामक एकीकृत डिजिटल पोर्टल के माध्यम से जारी किया जाएगा। यह प्रमाणपत्र उन निर्यातकों के लिए अनिवार्य है जो व्यापार समझौतों के तहत ओमान में सीमा शुल्क रियायतों का लाभ उठाना चाहते हैं।

डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में बताया कि 'ट्रेड कनेक्ट' भारतीय निर्यात के लिए मूलस्थान के सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रमाणपत्र जारी करने का एक एकीकृत डिजिटल मंच है। यह नई व्यवस्था 1 जून 2026 से भारत-ओमान व्यापार समझौते के प्रभाव में आने के साथ ही शुरू हो जाएगी। इस समझौते पर दिसंबर 2025 में हस्ताक्षर किए गए थे। यह कदम निर्यात प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने में सहायक होगा।

क्रिप्टो बाजार में भारी गिरावट

संस्थागत बिकवाली ने बिटकॉइन को 72,000 डॉलर के नीचे धकेला

नई दिल्ली ।

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में इन दिनों भारी उथल-पुथल देखी जा रही है। दुनिया की सबसे लोकप्रिय डिजिटल करेंसी बिटकॉइन, 72,000 डालर के अहम मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे फिसल गई है, जिसने निवेशकों और ट्रेडर्स के बीच खलबली मचा दी है। इस गिरावट की सबसे बड़ी वजह क्रिप्टो मार्केट से संस्थागत निवेशकों द्वारा अपना पैसा निकालना माना जा रहा है, जिसने बाजार के सेंटिमेंट को बुरी तरह प्रभावित किया है। स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ से आउटफ्लो बाजार में आई इस अचानक और तेज गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह स्पॉट बिटकॉइन से लगातार होने वाला भारी आउटफ्लो है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में इन ईटीएफ से करीब 2.8 बिलियन डॉलर का फंड बाहर निकाला जा चुका है। ब्लैकरॉक जैसे बड़े फंड्स से बड़े पैमाने पर हुई इस बिकवाली ने बाजार पर गहरा दबाव डाला है, जिससे बिटकॉइन के दाम तेजी से नीचे आ गए हैं। संस्थागत निवेशकों का यह कदम दर्शाता है कि वे फिलहाल जोखिम लेने से बच रहे हैं या मुनाफावसूली कर रहे हैं। मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस गिरावट के पीछे सिर्फ संस्थागत बिकवाली ही नहीं, बल्कि वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, बढ़ती ब्याज दरें और बड़े निवेशकों द्वारा मुनाफावसूली करना भी शामिल है। फिलहाल, ट्रेडर्स और आम निवेशकों को बाजार में अत्यधिक सावधानी

बरतने की सलाह दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ में दोबारा बड़े पैमाने पर निवेश शुरू नहीं होता या बाजार में स्थिरता नहीं आती, तब तक अस्थिरता बनी रह सकती है।

भारत-अमेरिका व्यापार समझौता अगले कुछ हफ्तों में होगा- राजदूत गोर

समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि दल अगले सप्ताह नई दिल्ली आएगा

नई दिल्ली ।

भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हाल ही में घोषणा की है कि भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौता अगले कुछ हफ्तों और महीनों में अंतिम रूप ले लेगा और उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। यह जानकारी उन्होंने यूएस-इंडिया ट्रस्ट इनिशिएटिव में अनुसंधान और नवाचार में साझेदारी को बढ़ावा देने के मुद्दे पर दी, जहां उन्होंने दोनों देशों के बीच नवाचार और निवेश से प्रेरित रणनीतिक साझेदारी पर भी जोर दिया। राजदूत गोर ने बताया कि इस समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की एक उच्चस्तरीय दल अगले सप्ताह नई दिल्ली पहुंच रहा है, ताकि व्यापार के अंतिम एक प्रतिशत पर चर्चा और निर्णय लिया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अमेरिका और भारत एक-दूसरे के सबसे बड़े व्यापार भागीदारों में बने हुए हैं। गोर ने कहा, महत्त्वपूर्ण बात यह है कि यह डिजिटल व्यापार और उन्नत विनिर्माण से लेकर ऊर्जा और उभरती प्रौद्योगिकियों तक, नवाचार, निवेश और उच्च-मूल्य वाले क्षेत्रों द्वारा तेजी से संचालित हो रहा है। उन्होंने बताया कि व्यापार में यह वृद्धि न केवल दोनों देशों की बड़ी कंपनियों को लाभ पहुंचा रही है, बल्कि स्टार्टअप्स और व्यक्तिगत उद्यमियों की भी मदद कर रही है। राजदूत गोर ने भारत की तकनीकी क्षमता की सराहना करते हुए कहा कि विशेष रूप से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जैसे उच्च शिक्षा संस्थानों में तकनीकी नवाचार अगले दो, पांच और दस वर्षों में वैश्विक मंच पर दिखाई देगा, जिनमें से कुछ नवाचार दुनिया भर के लोगों के लिए जीवन बदलने वाले हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि महत्त्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियां वैश्विक शक्ति संतुलन को नया आकार दे रही हैं और इस दिशा में नेतृत्व करने के लिए हमारे जैसी कोई बेहतर साझेदारी नहीं।

एनएफएचएस-6 में मोटापे-मधुमेह का बढ़ता बोझ, प्रगति के साथ चिंता

नई दिल्ली ।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-6 (एनएफएचएस-6) के ताजा आंकड़े भारत के बदलते स्वास्थ्य परिदृश्य की एक जटिल तस्वीर पेश करते हैं। जहां एक तरफ देश स्वास्थ्य बीमा कवरेज, टीकाकरण दरों और मातृत्व एवं बाल पोषण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरी ओर मोटापा और मधुमेह का बढ़ता प्रसार एक नई और गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बन गया है, जो कुपोषण और संचारी रोगों पर केंद्रित पुरानी व्यवस्था से गैर-संचारी रोगों (एनसीडी) की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत है। सर्वेक्षण के निष्कर्ष बताते हैं कि मोटापे का बढ़ता बोझ अब सार्वजनिक स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों दृष्टियों से चिंता का विषय है। शरीर का अत्यधिक वजन मधुमेह, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और कैंसर के बढ़ते जोखिम का एक प्रमुख कारक है। एनएफएचएस-5 (2019-21) और एनएफएचएस-6 (2023-24) के बीच मोटापे का प्रसार उल्लेखनीय रूप से बढ़ा है। 15 से 49 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं में मोटापे की शिकार महिलाओं का हिस्सा 24 फीसदी से बढ़कर 30.7 फीसदी हो गया है, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा 22.9 फीसदी से बढ़कर 27.3 फीसदी पर पहुंच गया है। इस सर्वेक्षण में 25 किग्रा/मीट या इससे अधिक के बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) को अधिक वजन या मोटापा परिभाषित किया गया है।

इस बढ़ती चुनौती के बीच, देश में वजन घटाने के उपचार और मेटाबोलिक स्वास्थ्य सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ी है। पिछले एक साल के दौरान इंजेक्टेबल जीएलपी-1 एगोनिस्ट जैसे मौनजारो, वेगोवी और ओजेम्पिक की बिक्री में 218 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।

एसबीआई ने फोनपे, क्रेडिट कार्ड रिवॉर्ड नियमों में किया बड़ा बदलाव

नए नियम 1 जुलाई 2026 से प्रभावी

नई दिल्ली ।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने अपने फोनपे एसबीआई कार्ड सेलेक्ट ब्लैक क्रेडिट कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। बैंक ने इस कार्ड से जुड़े रिवॉर्ड पॉइंट्स प्रोग्राम के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जो 1 जुलाई, 2026 से प्रभावी होंगे। इन संशोधनों से कार्डधारकों को मिलने वाले रिवॉर्ड पॉइंट्स में कमी आएगी। अब ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन शॉपिंग पर मिलने वाले 5 फीसदी रिवॉर्ड पॉइंट्स की मासिक सीमा 2,000 से घटाकर 1,000 कर दी गई है।

इसके अतिरिक्त, टोल, ज्वेलरी, स्कूल/कॉलेज फीस, गिफ्ट्स और फोनपे ऐप के बाहर किए गए यूटिलिटी, इंश्योरेंस या यूपीआई ट्रांजैक्शन पर अब कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं दिए जाएंगे।

फोनपे ऐप के जरिए यूटिलिटी, रिचार्ज या इंश्योरेंस पर कुल 2,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स की मौजूदा लिमिट को भी विभाजित कर दिया गया है; अब इंश्योरेंस पर अधिकतम 500 और अन्य कैटेगरी पर अधिकतम 1,500 पॉइंट्स ही मिलेंगे। हालांकि, सामान्य खर्चों पर 1 फीसदी रिवॉर्ड पॉइंट्स, फ्यूल सरचार्ज वेवर, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस (साल में 4 बार) और प्रायोरिटी पास मेंबरशिप जैसी सुविधाएं पहले की तरह ही मिलती रहेंगी। इस कार्ड की वार्षिक और रिन्यूअल फीस 1,499 रुपए है।

कर्नाटक के नए सीएम के सामने होंगी राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक चुनौतियां

कार्यभार संभालने से पहले शिवकुमार के सामने मंत्रियों की परिषद चुनने की चुनौती

नई दिल्ली।

कर्नाटक में बड़ी राजनीतिक हलचल के बीच सिद्दरमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और उम्मीद है कि डीके शिवकुमार राज्य के नए सीएम होंगे। कर्नाटक के नए सीएम के सामने कई चुनौतियां भी होंगी जिनमें राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक चुनौतियां हैं। इनमें नई कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातिगत समीकरणों को संतुलित करने से लेकर, वित्तीय दबाव के बीच कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मेकेदातु जलाशय मुद्दे को सुलझाना शामिल है। ये काम शिवकुमार के लिए मुश्किलों भरा रहने वाला है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक औपचारिक रूप से कार्यभार संभालने से पहले ही शिवकुमार के सामने मंत्रियों की परिषद चुनने की बड़ी चुनौती है। शिवकुमार के सामने सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौतियों में से एक अहिंदा के उस समर्थन आधार को बनाए रखना है, जिसे सिद्दरमैया ने बड़ी मेहनत से तैयार किया था। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के इस सामाजिक गठबंधन ने 2023 में कांग्रेस की सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई थी और यह पार्टी की चुनावी रणनीति का मुख्य केंद्र बना हुआ है।

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि उन्हें अहिंदा समुदायों को यह भरोसा दिलाना होगा कि उनके हितों की रक्षा आगे भी होती रहेगी। जरा सी भी अनदेखी या नाराजगी बीजेपी-जेडीएस को अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने का मौका दे सकती है। इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखना राजनीतिक रूप से बेहद जरूरी होगा। सिद्दरमैया के साथ तालमेल बिठाकर काम करने की शिवकुमार की क्षमता ही यह तय करेगी कि 2028 में कांग्रेस सत्ता की बागडोर दोबारा संभाल पाती है या नहीं। बता दें सिद्दरमैया ने राज्य की राजनीति में सक्रिय रहने का प्रण लिया है। कांग्रेस की मुख्य गारंटी योजनाओं को जारी रखते हुए राज्य के वित्त का प्रबंधन करना एक मुश्किलभरा काम साबित हो सकता है। सरकार पहले से ही पांच योजनाओं पर सालाना लगभग 51,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है, जिसमें गृह लक्ष्मी, शक्ति, अन्न भाग्य, युवा निधि और गृह ज्योति जैसी योजनाएं शामिल हैं। राजस्व जुटाना, बढ़ती सब्सिडी की प्रतिबद्धताएं और उधार लेने की सीमाएं मुख्य चिंताएं बनी रहेंगी लेकिन कल्याणकारी योजनाओं में कटौती करने से राजनीतिक जोखिम हो सकते हैं। कर संग्रह में सुधार, निवेश आकर्षित करना और खर्च को प्राथमिकता देना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। बेंगलुरु से बाहर विकास का विस्तार करना

और कृषि संबंधी चिंताओं को दूर करना एक और अहम क्षेत्र है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। भले ही बेंगलुरु निवेश, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक ध्यान के मामले में हावी बना हुआ है, लेकिन उत्तरी और ग्रामीण कर्नाटक के प्रतिनिधियों ने लगातार इन क्षेत्रों पर ज्यादा ध्यान देने की मांग की है। कई जिलों के किसानों को सूखे, सिंचाई की कमी, फसलों के नुकसान और बाजार की कीमतों में उतार-चढ़ाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।

वंदे मातरम् विवाद पर भूपेश बघेल का भाजपा को खुला चैलेंज, बोले- बिना देखे गाकर दिखाएं

रायपुर।

केरल में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् को लेकर छिड़े राजनीतिक विवाद के बीच छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। रायपुर में मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को खुली चुनौती देते हुए कहा कि वे एक साथ बिना देखे वंदे मातरम् गाकर दिखाएं। भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की परंपरा में वंदे मातरम् हमेशा से शामिल रहा है और पार्टी के कार्यक्रमों की शुरुआत इसी गीत से होती है। उन्होंने दावा किया कि जिला स्तर से लेकर बड़े आयोजनों तक कांग्रेस कार्यकर्ता नियमित रूप से वंदे मातरम् गाते हैं, जबकि भाजपा के लोग इस विषय पर केवल राजनीति करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के जिला, ब्लॉक और प्रदेश स्तर के कार्यक्रमों में वंदे मातरम् का गायन एक परंपरा है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग आज राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वे पहले कभी वंदे मातरम् गाते तक नजर नहीं आते थे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय प्रतीकों को राजनीतिक विवाद का विषय बनाने के बजाय उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अपने हालिया दिल्ली दौरे को लेकर भी भूपेश बघेल ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उनकी मुलाकात कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई। बघेल ने कहा कि बैठक में विशेष रूप से पंजाब की राजनीतिक स्थिति और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया। केंद्र में भाजपा सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर शुरू किए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भाजपा को जनसंपर्क अभियान अवश्य चलाना चाहिए, क्योंकि जनता उनके जवाब का इंतजार कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि महाजनसंपर्क अभियान के दौरान जनता भाजपा से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं और अन्य जनहित के मुद्दों पर सवाल पूछेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार को अब जनता के सवालों का जवाब देना होगा।

सड़कों पर उतरी कॉकरोच जनता पार्टी

पहला ग्राउंड कैंपेन इंटरनेट पर तेजी से फैला

पार्टी का दावा- वीडियो और तस्वीरों को अम्प्लिफाई कर प्रशासन पर बनाया जाएगा दबाव

नई दिल्ली।

देश के युवाओं ने अब जर्जर बुनियादी ढांचे और नागरिक समस्याओं के खिलाफ अपना रोष प्रकट करने का अनोखा और व्यंग्यात्मक तरीका ढूंढ लिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) अब सड़कों पर उतर आई है। उनका पहला ग्राउंड कैंपेन इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है और नगर निगमों की कार्यप्रणाली पर सीधा प्रहार कर रहा है। इस कैंपेन के तहत कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक देशभर में पोटहोल्स, कूड़े के ढेर, टूटे स्ट्रीटलाइट्स, सरकारी दफ्तरों में लापरवाही और अन्य नागरिक समस्याओं को रिकॉर्ड करके पार्टी को टैग कर रहे हैं। पार्टी का दावा है कि ये वीडियो और तस्वीरों को अम्प्लिफाई करके प्रशासन पर दबाव बनाया जाएगा। अभिजीत दीपके नामक व्यक्ति द्वारा शुरू की गई इस ऑनलाइन कॉकरोच जनता पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस तीन मिनट के वीडियो में एक व्यक्ति कॉकरोच के आकार का मुखौटा पहनकर शहर की सड़कों और नालियों के आसपास दिखाई देता है। वीडियो का मुख्य संदेश गंदगी, खुले नालों और खराब स्वच्छता व्यवस्था के खिलाफ जागरूकता फैलाना है। स्थानीय पार्षदों और अधिकारियों को टैग करते हुए उनके इलाकों की सबसे खराब सड़कों और जलभराव वाले क्षेत्रों के लिए व्यंग्यात्मक डिजिटल सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। इंस्टाग्राम और एक्स पर कॉकरोच फिल्टर का इस्तेमाल करते हुए युवा दूषित पानी, ट्रैफिक जाम, और टूटी सड़कें पर व्यंग्यात्मक रील्स बना रहे हैं। यह सब शुरू हुआ 15 मई 2026 को, जब भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और परजीवी कहकर संबोधित किया था। सीजेआई ने बाद में स्पष्टीकरण दिया कि उनका इशारा फर्जी डिग्री वाले लोगों की ओर था, न कि पूरे युवा वर्ग की ओर। लेकिन इस टिप्पणी ने सोशल मीडिया पर तूफान खड़ा कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी, नीट पेपर लीक, यूपीएससी की समस्याओं और युवा निराशा से जूझ रहे लाखों युवाओं ने इसे अपना अपमान माना। इसी गुस्से और व्यंग्य को पकड़ते हुए बोस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस के छात्र अभिजीत दीपके ने 16 मई

को कॉकरोच जनता पार्टी की घोषणा की। +कॉकरोच+ शब्द को उन्होंने अपनाया और इसे प्रतिरोध का प्रतीक बना दिया। दीपके, महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से हैं। उन्होंने पुणे में जर्नलिज्म की पढ़ाई की और आप के साथ 2020-2023 तक सोशल मीडिया वॉलंटियर के रूप में काम किया था। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की तेज रफ्तार ने सरकार को चिंता में डाल दिया है। आईबी के इनपुट पर मूल अकाउंट को सेक्शन 69ए के तहत भारत में ब्लॉक करवा दिया।

केजरीवाल बोले- शिक्षा व्यवस्था माफिया के चंगुल में

वायुसेना के विमान से प्रश्नपत्र पहुंचाने के प्रस्ताव पर उठाए सवाल

नई दिल्ली।

पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने नीट-यूजी परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए वायुसेना के विमानों के इस्तेमाल संबंधी प्रस्तावित व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केवल प्रश्नपत्रों के परिवहन का तरीका बदलने से पेपर लीक जैसी समस्याएं खत्म नहीं होंगी और इसके लिए मजबूत एवं पारदर्शी व्यवस्था की आवश्यकता है। सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी अपने बयान में केजरीवाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता पेपर लीक रोकने की बजाय दिखावटी उपायों पर केंद्रित दिखाई दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि देश की शिक्षा व्यवस्था परीक्षा माफिया के प्रभाव में आ चुकी है और इसे सुधारने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयासों की जरूरत है। गौरतलब है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित नीट-यूजी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक होने के बाद रद्द कर दी गई थी। अब इसकी पुनर्परीक्षा 21 जून को प्रस्तावित है।

इसी बीच, देशभर में आयोजित सीयूईटी-यूजी परीक्षा के दौरान भी कुछ केंद्रों पर तकनीकी समस्याओं की शिकायतें सामने आई हैं। आप की वरिष्ठ नेता आतिशी ने भी वाराणसी के एक परीक्षा केंद्र पर कथित सर्वर समस्या का मुद्दा उठाया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में छात्रों को परीक्षा शुरू होने में हुई देरी से परेशान दिखाया गया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने परीक्षा प्रबंधन पर सवाल उठाए और कहा कि छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में लापरवाही स्वीकार्य नहीं है।

प्रधानों की भुगतान संबंधी दिक्कतें जल्द होंगी दूर-कमलेश पासवान

बाराबंकी ।

भारत सरकार में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने बाराबंकी जनपद का दौरा किया। इस दौरान वह भाजपा के पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के प्रधानों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) 'वीबी-जी राम जी' के कार्यान्वयन की समीक्षा की। केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि मनरेगा में कई प्रकार की त्रुटियां थीं और बड़े स्तर पर अनियमितताओं एवं घोटालों की शिकायतें सामने आ रही थीं। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 'वीबी-जी राम जी' योजना लेकर आई है। उन्होंने कहा कि इस नई योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर वह विभिन्न जिलों का दौरा कर अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनने वाली नई कार्ययोजनाओं पर भी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश पर केंद्र सरकार के मंत्री और विभागीय अधिकारी जिला स्तर पर पहुंचकर योजनाओं की प्रगति का आकलन कर रहे हैं। इसी क्रम में वह बाराबंकी पहुंचे हैं।केन्द्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि बैठक में बड़ी संख्या में प्रधान शामिल हुए, जिनसे सीधे संवाद कर उनकी समस्याओं और सुझावों को सुना गया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ग्राम प्रधानों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाए।

अभिषेक पर हुआ हमला, कपड़े फाड़े

टीएमसी सांसद बोले- ऐसे कायराना हमलों से डरने वाले नहीं

कोलकाता।

पश्चिम बंगाल के सोनारपुर इलाके में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर अंडे फेंके जाने और हमला करने से राजनीतिक माहौल गरमा गया है। आरोप है कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक पर जानलेवा हमला किया गया, वे चुनावी हिंसा में घायल पार्टी कार्यकर्ताओं का हाल जानने पहुंचे थे।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सांसद अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में हाल ही में हुई चुनावी हिंसा में घायल हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने और उनका हालचाल जानने पहुंचे हुए थे। इसी बीच माहौल तनावपूर्ण हो गया और देखते ही देखते हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया है, जैसे ही अभिषेक का काफिला सोनारपुर पहुंचा, वहां पहले से ही मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी शुरू कर दी, और देखते

ही देखते हिंसक झड़प शुरू हो गई। भीड़ में से ही कुछ ने सांसद पर अंडे फेंके और उनके साथ धक्का-मुक्की भी की, जिससे अभिषेक की शर्ट फट गई।

हेलमेट पहना सुरक्षित बाहर निकाला

बताया जा रहा है कि स्थिति बेकाबू होती देख सुरक्षाकर्मियों ने अभिषेक बनर्जी को हेलमेट पहनाया और सिर को सुरक्षित रखने की कोशिश की। आनन-फानन में हेलमेट पहना कर किसी तरह उन्हें उग्र भीड़ से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक ने मीडिया से बात करते हुए अपनी आपबीती सुनाई। आक्रोश व्यक्त कर रहे अभिषेक ने कहा, पूरी तैयारी के साथ आए ये लोग अस्त्रल में मुझे जान से मारना चाह रहे थे। उन्होंने हमला किया और शर्ट तक फाड़ दी। उन्होंने पुलिसकर्मी तैनात नहीं होने पर भी हैरानी जताई। अभिषेक बनर्जी ने हमलावर विपक्षी दलों को ललकारते हुए कहा, टीएमसी ऐसे कायराना हमलों से डरने वाली नहीं है और वे जनता की लड़ाई को आगे भी जारी रखेंगे।

राष्ट्रपति ट्रम्प की बेटी टिफनी ने मोहब्बत की निशानी ताजमहल का किया दीदार

पति के साथ सेंट्रल टैंक पर बेंच पर बैठ हाथों में हाथ डालकर फोटो कराया शूट

आगरा।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी टिफनी ट्रम्प ने शनिवार को मुगल बादशाह के बनवाए मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार किया। होटल अमर विलास पहुंचते ही, उन्होंने पहले ताजमहल देखने की इच्छा जताई। सुरक्षा एजेंसियों ने इस पर तत्काल उनकी विजिट की व्यवस्था की। टिफनी ने ताजमहल को अद्भुत और अनोखा बताया और कहा कि दुनिया में इसकी कोई मिसाल नहीं।

बता दें निजी यात्रा पर आईं टिफनी के साथ उनके पति माइकल बाउलस भी आए हैं। दोनों ने सेंट्रल टैंक पर बेंच पर बैठकर हाथों में हाथ डालकर फोटो शूट कराया। टिफनी चार्टर्ड प्लेन से शनिवार सुबह दिल्ली से खेरिया एयरपोर्ट पर उतरीं। यहां से वह ताजमहल के पूर्वी गेट स्थित होटल अमर विलास पहुंची। उनका

लंच के बाद शाम पांच बजे ताजमहल देखने का कार्यक्रम था। होटल पहुंचने के बाद गायक व मॉडल टिफनी ने लंच से पहले ताजमहल देखने की इच्छा जता दी। इस पर तुरंत ताजमहल जाने की व्यवस्था की गई।

रिपोर्ट के मुताबिक टिफनी सुबह 11:50 पर ताजमहल पहुंचीं। फोरकोर्ट से ताजमहल नजर आते ही वह उसकी खूबसूरती देखकर बहुत खुश नजर आईं। गाइड ने उन्हें शाहजहां द्वारा मुमताज की याद में ताजमहल बनवाने, ताजमहल का निर्माण 22 सालों में 20 हजार मजदूरों द्वारा करने, औरंगजेब द्वारा शाहजहां को आगरा किला में बंदी बनाने और वहीं उसकी मौत होने की जानकारी दी। टिफनी ने पूछा कि ताजमहल के निर्माण को संगमरमर कहां से आया था। गाइड ने मकराना से संगमरमर आने की जानकारी दी। विजिट के दौरान टिफनी के पति बाउलस ने भी इतिहास में काफी रुचि दिखाई। वह करीब 50 मिनट तक ताजमहल में रहीं और 12:40 बजे होटल अमर विलास लौट गईं।

जहरीली शराब पीने से अवैध शराब विक्रेता राहुल क्षीरसागर की भी मौत

पुलिस प्रशासन ने तीन पुलिस अधिकारियों को किया निलंबित

पुणे।

महाराष्ट्र के पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ में जहरीली शराब पीने से मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। इस पूरे मामले में अवैध शराब विक्रेता राहुल क्षीरसागर की भी जहरीली शराब पीने से मौत होने की जानकारी सामने आई है। 13 मई को राहुल क्षीरसागर के खिलाफ शराब बिक्री के संबंध में हडपसर पुलिस स्टेशन में मामला भी किया गया था। पुणे के हडपसर इलाके के पांढरे माला क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से कम से कम 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। स्थानीय लोगों के मुताबिक शराब पीने के कुछ ही देर बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। लोगों को उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुणे पुलिस प्रशासन ने तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए अधिकारियों में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मोगले, सहायक पुलिस निरीक्षक हसीना सिकलगार और पुलिस उपनिरीक्षक हसन मुलाणी शामिल हैं। तीनों अधिकारी हडपसर पुलिस स्टेशन और उससे जुड़े अपराध जांच तंत्र में कार्यरत थे। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अवैध रूप से जहरीली देसी शराब तैयार की और उसमें विषैले रसायन मिलाकर उसका परिवहन एवं वितरण किया। आरोपियों को यह जानकारी थी कि इस शराब के सेवन से लोगों की जान जा सकती है। इसके बावजूद वे सुनियोजित तरीके से जहरीली शराब बेचकर कई लोगों की मौत का कारण बने।

महाराष्ट्र में बस ने बाइक को मारी टक्कर, चार लोगों की मौत

उत्तेजित भीड़ ने बस को नुकसान पहुंचाया, पुलिस ने हालात नियंत्रण में किए

मुंबई।

महाराष्ट्र के परभणी जिले में एक बाइक और एक निजी बस के बीच हुई भीषण टक्कर में चार लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना व्यस्त परभणी-पाथरी मार्ग पर राहुल जिनिंग के पास अंधारवाड़ मारुति मंदिर क्षेत्र में हुई। अधिकारियों ने बताया कि टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। अधिकारियों के मुताबिक श्रीनिधि ट्रेवल्स की बस परभणी से पुणे जा रही थी। इसी दौरान बस ने राहुल जिनिंग के पास आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक सवार चारों लोगों की मौत हो गई। मृतकों में शुभम अप्पाराव दाहे (30), विष्णु गोरे (28), प्रह्लाद अशोकराव कुटे (29) और नवनाथ शामराव जाधव (38) हैं। तेज टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि कुछ ही देर बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई जब उत्तेजित भीड़ ने दुर्घटनाग्रस्त निजी बस को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने हालात को नियंत्रण में किया। दुर्घटना के कारण परभणी-पाथरी राजमार्ग पर अस्थायी रूप से यातायात बाधित हुआ, जिससे यातायात जाम हो गया और यात्रियों को देरी का सामना करना पड़ा। दुर्घटना के बाद पुलिस ने सभी शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों के परिजनों और आम नागरिकों की भारी भीड़ देर रात तक अस्पताल परिसर में जमा रही। एक ही गांव के चार लोगों की इस हादसे में मौत से मनावत कस्बे और आसपास के इलाकों में गहरा शोक छा गया। पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।

होर्मुज से निकलने भारत ने एक्टिव किया सीक्रेट प्लान! 13 अभी भी फंसे

नई दिल्ली।

ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच छिड़े युद्ध के बाद से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया के सबसे संवेदनशील और खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक बन गया है। हाल ही में सीजफायर लागू होने के बावजूद, इस मार्ग पर जहाजों की आवाजाही अब भी बड़े पैमाने पर ठप है। ओमान और ईरान के बीच स्थित इस संकरे समुद्री रास्ते से दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। वैश्विक ऊर्जा बाजार में मचे इस भारी संकट और उथल-पुथल के बीच, भारत अपने जहाजों को वहां से सुरक्षित बाहर निकालने के लिए एक बेहद खास और गोपनीय रणनीति पर काम कर रहा है।

जानकारी के अनुसार, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज क्षेत्र में वर्तमान में 13 भारतीय व्यावसायिक जहाज मौजूद हैं। इस बेड़े में एक एलपीजी टैंकर, पांच कच्चे तेल के टैंकर, एक केमिकल टैंकर, तीन कंटेनर जहाज, दो बल्क कैरियर और एक ड्रेजर शामिल हैं। भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता इन सभी जहाजों और उन पर सवार चालक दल को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित बाहर निकालना है।रणनीति की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार ने इसके संचालन की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह गोपनीय रखा है। हालांकि, यह स्पष्ट किया गया है कि इस पूरे अभियान का समन्वय विदेश मंत्रालय के जरिए किया जा रहा है। कौन सा जहाज पहले इस खतरे वाले क्षेत्र से बाहर निकलेगा, इसकी प्राथमिकता पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा उर्वरक मंत्रालय के साथ मिलकर तय की जा रही है। इसी आपसी तालमेल के आधार पर जहाजों को धीरे-धीरे सुरक्षित निकाला जा रहा है।

सरकार के इन प्रयासों का सकारात्मक असर भी दिखाई देने लगा है। हाल ही में करीब 2,70,000 मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर आ रहा निसोस केरोस नामक क्रूड ऑयल टैंकर सफलतापूर्वक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने में कामयाब रहा, जिसके जून की शुरुआत तक विशाखापत्तनम पहुंचने की उम्मीद है। अब तक 14 जहाज इस खतरनाक मार्ग को सुरक्षित पार करके भारत लौट चुके हैं, जबकि 11 जहाज अभी भी फारस की खाड़ी क्षेत्र में मौजूद हैं और उन पर नजर रखी जा रही है।

पब्लिक डोमेन में उपलब्ध शिप ट्रैकिंग डेटा से जहाजों की सुरक्षा को होने वाले संभावित खतरे पर अधिकारियों का कहना है कि ये कमर्शियल ऐप्स हैं, जिनका कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। सार्वजनिक डेटा का उपयोग कैसे होगा, यह उपयोगकर्ता की नीयत

पर निर्भर करता है, लेकिन फिलहाल यह डेटा सरकार को जहाजों की स्थिति ट्रैक करने में सहायता दे रहा है।

गौरतलब है कि युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई में जहाजों को निशाना बनाना शुरू किया था, क्योंकि भौगोलिक स्थिति के कारण इस रूट पर उसका दबदबा है। इसी डर से दुनिया की कई बड़ी अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने इस मार्ग से अपने जहाजों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी है।

स्वात्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक कजोड़मल मीना के लिए स्काईटक प्रिन्टर्स, 111, नवाब कल्लन का बाग, एमएलए क्वार्टर, नीयर समाचार जगत, एमआई रोड, जयपुर से मुद्रित एवं 303, भव्य टॉवर, कबीर मार्ग, बनीपार्क जयपुर से प्रकाशित।
(इस अंक में प्रकाशित समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के तहत उत्तरदायी) समस्त विवादों का न्यायिक क्षेत्राधिकार जयपुर शहर होगा। RNI No. RAJHIN/2001/05699 मो. नं. 9928078717